04 -विदेश नीति के कठिन दौर में एकजुटता जरूरी

05 - परीक्षा में दिव्यांगों के लेखक बदलने के सवाल पर विचार

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 05 जनवरी, 2026

06 - हिन्दू सम्मेलन की दिव्यता-भव्यता और उमड़े सैलाब से धारा नगरी ने...

07 - फार्मर आईडी बनवाने की कलेक्टर ने किसानों से की अपील

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 125, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

वेनेजुएला पर ट्रंप के प्लान से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी?

एंथनी ज़र्चर

वेनेजुएला में डर और सदमे का माहौल बनाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्र-निर्माण के काम में उतरते दिख रहे हैं। शनिवार सुबह अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में एक असाधारण प्रेस कॉन्फ़्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी बलों ने काराकास में रातों-रात की गई कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उनकी एक टीम वेनेजुएला के लोगों के साथ मिलकर काम करेगी और संकटग्रस्त देश का नियंत्रण संभालेगी। इस टीम में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, 'हम देश को तब तक चलाएंगे, जब तक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता।'

हालांकि, 'देश चलाने' का असल मतलब क्या होगा, यह साफ़ नहीं है. लेकिन यह फ़ैसला ट्रंप की नीति में अचानक आए बदलाव को दिखाता है, जिसमें विरोधाभास और बड़ी चुनौतियां शामिल हैं।

एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 'हमेशा चलने वाले युद्धों' के ख़िलाफ़ कैंपेन किया, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका की पिछली कोशिशों की कड़ी आलोचना की और 'अमेरिका फ़र्स्ट' विदेश नीति लागू करने का वादा किया, अब वही अपने राष्ट्रपति पद को एक ऐसे दक्षिण अमेरिकी देश के सफल पुनर्निर्माण को लेकर दांव पर लगा रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है और जिसकी राजनीतिक स्थिरता दशकों की तानाशाही से कमज़ोर है। फिर भी ट्रंप लगातार आशावादी बने रहे। कि उनके प्रशासन का 'जीतने का रिकॉर्ड पूरी तरह बेदाग़' है और यह मामला भी अलग नहीं होगा। उन्होंने वेनेजुएला के जर्जर औद्योगिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को शामिल करने, अमेरिकी पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए धन उपलब्ध कराने और वेनेजुएला के लोगों को लाभ पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हम ज़मीन पर सैनिक भेजने से नहीं डरते कल रात भी ज़मीन पर हमारे सैनिक थे।'

इराक़ पर अमेरिकी हमले के कड़े आलोचक रहे ट्रंप को अब इराक़ युद्ध के अमेरिकी रणनीतिकारों में से एक, पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के शब्दों पर ध्यान देना होगा, 'अगर आप इसे बिगाड़ते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी।'

अमेरिका ने वेनेजुएला के भविष्य को नया रूप दिया है, चाहे यह बेहतर के लिए या बदतर के लिए। ट्रंप लगभग एक साल पहले पद संभालते समय खुद को शांति का दूत बताते थे। लेकिन बीते एक साल में उन्होंने दिखाया है कि वह दुनियाभर में सैन्य ताक़त इस्तेमाल करने को तैयार हैं। 2025 में उन्होंने ईरान में परमाणु ठिकानों, कैरिबियाई क्षेत्रों में संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े जहाज़ों, यमन में विद्रोही बलों, सोमालिया में सशस्त्र समूहों और इराक़ में इस्लामी चरमपंथियों को निशाना बनाया। इन पिछली कार्रवाइयों में ज़्यादातर मिसाइलों और विमानों का इस्तेमाल हुआ और अमेरिकी बलों को सीधे ख़तरे से दूर रखा गया। इसके मुक़ाबले वेनेजुएला र ट्रंप की कार्रवाई और उस देश के भविष्य को लेकर उनकी प्रतिबद्धताएं काफ़ी अलग हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि उनका लक्ष्य 'वेनेजुएला को फिर से महान बनाना' है। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर ट्रंप की कार्रवाई की तुरंत आलोचना की। ग्रीन कभी ट्रंप की वफ़ादार रही थीं।

उन्होंने लिखा, 'हमारी अपनी सरकार की कभी न ख़त्म होने वाली सैन्य आक्रामकता और विदेशी युद्धों के समर्थन को लेकर अमेरिकियों की नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि हमें इसकी क़ीमत चुकानी पड़ती है और रिपब्लिकन व डेमोक्रेट, दोनों दल वॉशिंगटन की सैन्य मशीनरी को हमेशा चलते रहने के लिए फंड देते हैं। मागा के कई लोगों ने सोचा था कि उन्होंने इसे ख़त्म करने के लिए वोट दिया है, लेकिन हम ग़लत थे।'

ट्रंप के एक और प्रमुख आलोचक, केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने मादुरो की गिरफ़्तारी के लिए दिए गए क़ानूनी तर्क, यानी हथियारों और कोकीन की तस्करी के आरोपों की तुलना ट्रंप की उस दलील से की जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अभियान ज़ब्त किए गए अमेरिकी तेल को वापस लेने और फ़ेंटानिल उत्पादन रोकने के लिए था। हालांकि ज़्यादातर रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति के समर्थन में खड़े दिखे। हाउस कार्रवाई को 'निर्णायक और न्यायसंगत' बताया। स्पीकर माइक जॉनसन ने एक 'आपराधिक शासन' के ख़िलाफ़ की गई सैन्य कार्रवाई बताया।

प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में की गई कार्रवाई उनकी 'अमेरिका फ़र्स्ट' प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इससे अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है और तेल की स्थिर आपूर्ति मिलती है। उन्होंने उन्नीसवीं सदी की शुरुआत के 'मुनरो डॉक्ट्रिन' को फिर से सामने रखा और उसे नया नाम दिया 'डोनरो डॉक्ट्रिन।' मुनरो सिद्धांत 19वीं सदी की शुरुआत की एक अमेरिकी विदेश नीति थी। इसका मानना था कि पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका महाद्वीप को यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कि वेनेजुएला पर कार्रवाई से अब पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व पर कभी सवाल नहीं उठेंगे। नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मक़सद 'व्यापार, क्षेत्र और संसाधनों की सुरक्षा करना है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल में हैं।' उन्होंने पश्चिमी गोलार्ध को अमेरिका का 'घरेलू क्षेत्र' बताया।

हालांकि, मादुरो को पकड़ने के ट्रंप के फ़ैसले से वैश्विक राजनीति और दुनिया की अन्य प्रमुख सैन्य शक्तियों के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़े सवाल खड़े होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस घटना पर हैरानी जताई और इसे एक संप्रभु देश पर लापरवाह हमला बताकर इसकी निंदा की।

बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसी तरह की निंदा की थी। अब ट्रंप प्रशासन इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, जो कई बार रूस के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ दिखा है। सेंट्रिस्ट रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन ने ट्रंप की कार्रवाई से जाने वाले संदेश को लेकर चिंता जताई है. बेकन इस साल के अंत में राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपनी ग़ैरक़ानूनी और बर्बर सैन्य कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए करेगा, या चीन ताइवान पर हमले को जायज़ ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

अनंत है अतिक्रमण के विचार की परिधि
इसलिए दूसरे के हिस्से की जगह चाहिए
फिर उसकी स्वतंत्रता
फिर उसका समूचा जीवन
वासनाएँ नए क्षेत्रों में करती हैं घुसपैठ
सिद्धांत और सुभाषित बदलने लगते हैं
हथियारों में
फिर मारने की चीज़ के बारे में
लंबे प्रचार के बाद बताया जाता है
कि वह बचाने की चीज़ है
जैसे जिसके पास बंदूक है वही अमर है

कितना दबाया है दूसरे के जीवन का रक़बा
और पृष्ठभूमि में से झाँकती हैं कितनी वस्तुएँ
इन बातों से ही बनने लगती है फिर
इस संसार में किसी की भी आदरणीय पहचान।

- कुमार अंबुज

बनारस के जानल चाहत होवे तो बनारस आवै का पड़ी

● मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया शुभारंभ

वाराणसी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 11 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कई राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव से अपने भाषण की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर, गिरीश यादव, वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण, वॉलीबॉल एसोसिएशन के अधिकारीगण, देशभर से आए सभी खिलाड़ी काशी के मेरे परिवारजनों को नमस्कार किया। मोदी ने कहा कि आज काशी सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत के बाद इस टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं।

वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है, टीम फर्स्ट

आगे मोदी ने कहा कि साथियों वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट्स नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल हैं। यह सहयोग का खेल और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है, यानी बाल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है, टीम फर्स्ट, भले ही हर कोई अलग-अलग स्किल का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल टीम में बहुत से बातें कॉमन देखता हूं।

बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी दिए हैं

साथियों हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है... बनारस के जानल चाहत होवे तो बनारस आवै का पड़ी, तो आप लोग बनारस आ गए हैं और बनारस जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, कबड्डी ऐसे कई खेले यहां बहुत मशहूर हैं। बनारस में कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ शिक्षण संस्थानों के खिलाड़ी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहते हैं और काशी तो हजारों वर्षों से उन सबका सत्कार करती आई है, जो ज्ञान और कला के लिए यहां जाते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा।

संभल में 2 मस्जिदें, एक मदरसा तोड़ा

एक मस्जिद को रातभर में लोगों ने खुद ढहाया

● दूसरे पर भी ऐक्शन, चला प्रशासन का बुलडोजर

संभल (एजेंसी)। संभल में 2 अवैध मस्जिदों और एक मदरसे को ढहा दिया गया है। एक मस्जिद को बुलडोजर एक्शन से पहले गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रातभर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची, तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था। यह देखकर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा- भगवान ने इन

लोगों को सद्बुद्धि दी कि इन्होंने खुद-ब-खुद अवैध निर्माण को तोड़ लिया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से तीन घंटे में मलबा हटाया। यह मस्जिद असमोली थाने के हाजीपुर गांव में 1339 वर्ग मीटर (डेढ़ बीघा) क्षेत्र में बनी थी। मलबा हटाने के बाद इसी गांव में 500 मीटर दूर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची। ढोल पिटवाकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुनादी कराई गई। तीन बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को तोड़ा जा रहा है। डीएम-एसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। मदरसे पर कार्रवाई के दौरान ही यहां से 11 किमी दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।

मुख्यमंत्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल

सोमनाथ हमारे आत्मबल और अविनाशी विश्वास का है प्रतीक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्रीमहाकाल और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे प्रदेश में विद्यमान है और प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। बार-बार ध्वस्त होकर भी सोमनाथ का पुनर्निर्माण यह उद्घोष है कि, शिव शाश्वत हैं, हमारी आस्था अडिग है और सनातन की चेतना अमर है।

सोमनाथ हमारे आत्मबल, पुनर्जागरण और अविनाशी विश्वास का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को आर्ट ऑफ़ लिविंग संस्था एवं भोपाल उत्सव मेला की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूद्र पूजा और मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के रवीन्द्र भवन- मुक्ताकाश परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे

थे। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, भोपाल उत्सव मेला के श्री मनमोहन अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता श्री माखन सिंह और श्री राहुल कोठारी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिव ही सत्य और सनातन हैं। पंच महाभूतों से बने हमारे शरीर का शिव ही सनातन संस्कृति की मूल अवधारणाओं से परिचय कराते हैं। शिव ही हमारे विकारों का संहार करते हैं। सनातन के विरोध का भाव रखने वाली संस्कृतियां,वर्तमान में स्वयं आतंरिक संकट से ग्रस्त हैं। जबकि सदैव विश्व के कल्याण की कामना करने वाली भारतीय संस्कृति, संसार को एक परिवार मानते हुए आगे बढ़ रही है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां एक ओर श्री सोमनाथ महादेव का पुनर्निर्माण कराया वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर की स्थापना की। उज्जैन में महाकाल जन-जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान हैं। यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि सनातन आदि और अनंत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आध्यात्मिक ज्ञान, उनकी आत्मीयता और मानवमात्र के प्रति प्रेम, सम्मानीय है। उनके द्वारा प्रसारित, सांस लेने की लयबद्ध सुदर्शन क्रिया की तकनीक ने कई लोगों के जीवन से तनाव, चिंता और अवसाद जैसे जटिल विकारों का निदान किया है।

इंदौर का जल संकट 'क्षेत्रीय महामारी घोषित' आईसीएमआर-एम्स की जांच

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच टीमें पहुंची, प्रशासन अलर्ट मोड पर

इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से फैले संक्रमण ने गंभीर रूप ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे 'क्षेत्रीय महामारी' घोषित कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संज्ञान लेते हुए अलग-अलग विशेषज्ञ टीमों को जांच के लिए इंदौर भेजा है। आईसीएमआर कोलकाता, एम्स भोपाल और एनआईआरबीआई की टीमें शहर में पहुंचकर सैंपल और मरीजों की स्थिति का अध्ययन कर रही हैं।

नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन बैक्टीरियल इंफेक्शन (कोलकाता) से

आए दो वैज्ञानिकों ने भी मौके पर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में नर्मदा जल को पीने योग्य नहीं पाया गया। पानी के सैंपलों में फीकल कोलीफार्म, ई-कोलाई, विक्रियो और प्रोटोजोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। गंदा पानी पीने से बीमार हुए लोगों का इलाज निजी अस्पतालों के साथ-साथ एमवाय अस्पताल में भी किया जा रहा है। मरीजों की कल्चर रिपोर्ट में हैजा की आशंका जताई जा रही है। सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने बताया कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है।

कलेक्टर-निगम आयुक्त का निरीक्षण

भागीरथपुरा में रविवार को कलेक्टर शिवम वर्मा और नवागत नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों के अमले के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात की गहन समीक्षा की। इस दौरान आईसीएमआर कोलकाता की टीम के साथ भी बीमारी के कारणों और नियंत्रण उपायों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मरीजों के उपचार और निगरानी के लिए प्रशासन द्वारा तीन स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। पहले स्तर पर क्षेत्र में बीमारी के लक्षण वाले लोगों की पहचान कर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दूसरे स्तर पर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। जबकि, तीसरे स्तर पर उपचार के बाद घर लौट चुके मरीजों की सेहत पर भी नियमित नजर रखी जा रही है।

नगर निगम का अमला क्षेत्र में लगातार सर्वे और रिंग सर्वे कर रहा है। जलापूर्ति लाइनों में पाए गए लीकेज की मरम्मत कर दी गई है तथा पेयजल की शुद्धता के लिए क्लोरीनेशन किया जा रहा है। घर-घर सुरक्षित पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गुलियन-बैरे सिंड्रोम का कोई मामला सामने नहीं आया और नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 25 °c

न्यूनतम 22°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 05 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

माँ नर्मदा विचार कुंभ

चंद्रशरण भार्गव

(स्वतंत्र पत्रकार,स्तंभकार एवं लेखक)

सरदार सरोवर बाँध से विकास को गति मिली है

सरदार सरोवर बाँध को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' के माध्यम से वर्षों से विरोध किया जाता रहा है । यह विरोध विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा है। वहीं माँ नर्मदा विचार कुंभ के माध्यम से पर्यावरणविद् सचिन दवे ने यह तर्क सामने लाया कि इस विरोध के समानांतर बाँध से जुड़े योजनाबद्ध विकास, सिंचाई, बिजली उत्पादन और रोजगार सृजन जैसे सकारात्मक पहलुओं को पर्याप्त रूप से सामने नहीं लाया गया । वर्षों से जनता विकास की बाट जोह रही है ।

देश में राइट (दक्षिणपंथ) और लेफ्ट (वामपंथ) विचारधाराओं के बीच लंबे समय से वैचारिक मतभेद रहे हैं। बाँध के संदर्भ में भी यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वामपंथी दृष्टिकोण जहाँ विरोध और संघर्ष को प्राथमिकता देता रहा है, वहीं संघ एवं उससे प्रेरित संगठनों ने विकास के साथ समाधान और पुनर्वास को केंद्र में रखने की बात कही है।

इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मध्यप्रदेश की जीवनरेखा मानी जाने वाली माँ नर्मदा पर निर्मित सरदार सरोवर बाँध है। एक ओर वामपंथी विचारधारा से प्रेरित मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से इस बाँध का विरोध किया, जबकि दूसरी ओर विद्यार्थी परिषद एवं संघ विचारधारा से जुड़े पर्यावरणविद् सचिन दवे ने धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में आयोजित नर्मदा विचार कुंभ के माध्यम से सरदार सरोवर बाँध से होने वाले विकास की वास्तविकता को जन-जन तक पहुँचाया। साथ ही उन्होंने कुक्षी क्षेत्र में पुनर्वास एवं बसाहट से जुड़े विषयों पर जनजागरण का कार्य भी किया।

विकास का पक्ष: विचार कुंभ की प्रस्तुति

माँ नर्मदा विचार कुंभ के आयोजक एवं पर्यावरणविद् सचिन दवे ने धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से सरदार सरोवर बाँध से हुए विकास को जन-जन तक पहुँचाया। उन्होंने कुक्षी क्षेत्र में पुनर्वास एवं बसाहट को लेकर जन-जागरण करते हुए यह बताया कि बाँध के कारण क्षेत्र में आधारभूत संरचना, आजीविका और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

सचिन दवे, जो पिछले 26 वर्षों से शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्होंने नर्मदा एवं शिप्रा नदियों के संरक्षण को लेकर एनजीटी में याचिकाएँ भी

दायर की हैं। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दोनों नदियों के लिए हजारों करोड़ रुपये के विकास एवं संरक्षण कार्य प्रारंभ किए गए हैं।

सरदार सरोवर बाँध से हुआ समग्र विकास

सरदार सरोवर बाँध के निर्माण से क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। सड़कों, आवासों, दुकानों, बस स्टैंड और नए आवासीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही आर्थिक समृद्धि को भी मजबूती मिली है।

विचार कुंभ में प्रस्तुत तथ्य

कृषि एवं सिंचाई- सरदार सरोवर से मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा मिली, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।

बिजली उत्पादन- जलविद्युत परियोजना से मध्यप्रदेश को लगभग 1400 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है, जिससे औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ।

मध्य प्रदेश ओर गुजरात कृषि क्षेत्र एवं सिंचाई क्षेत्र में सशक्त हुए हैं 2.5 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा बढ़ी है मालवा एवं निमाड़ में 15 से 20त्न खेती योग्य भूमि सिंचित होती थी जो वर्तमान में परियोजना के बनने के बाद 60 से 70 प्रतिशत भूमि सिंचित होती है

मालवा में 2010 में गेहूं का उत्पादन 15 से 20 औसत प्रति था वर्तमान में यह 40 प्रति हेक्टेयर हो गया है।

ग्रामीण विकास- सड़कों, आवासों, बस स्टैंड और नए आवासीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जिससे जीवन स्तर बेहतर हुआ।

पर्यटन विकास- सरदार सरोवर बाँध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण नर्मदा क्षेत्र पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा। होटल, गेस्टहाउस और स्थानीय रोजगार में वृद्धि हुई।

पर्यावरण संरक्षण- नर्मदा घाटी में वनों, वन्यजीवों और जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास तेज हुए। अनुमानतः पर्यटन से संबंधित उद्योगों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे होटल व्यवसाय, गाइड, परिवहन और खुदरा व्यापार को लाभ मिला है।

सरदार सरोवर बाँध एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। इस परियोजना ने न केवल जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन को सुदृढ़ किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नर्मदा नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में जलवायु संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा मिला है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है और क्षेत्र को नई पहचान प्राप्त हुई है।

माँ नर्मदा विचार कुंभ में प्रस्तुत विचारों ने इस बहस को नया आयाम देते हुए यह संदेश दिया कि बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन केवल विरोध या समर्थन के एकतरफा दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाधान, पुनर्वास और समग्र विकास के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ाया राजस्थान का संदिग्ध मौलवी

● गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट मोड पर आईं देश की जांच एजेंसियां

जैसलमेर (एजेंसी)। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के जिले जैसलमेर में एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड ने संदिग्ध मौलवी को पकड़ा है। गणतंत्र दिवस से पहले हुई इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आतंकवादी गतिविधियों के

खुफिया इनपुट के आधार पर टीम ने शनिवार को तनोट-किशनगढ़ क्षेत्र में कुरिया बेरी गांव में दबिश दी थी। मौलवी को जयपुर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार, आतंकवादी गतिविधियों के शक में पकड़ा गया अली खान बीकानेर में छत्तरगढ़ तहसील का रहने वाला है। एटीएस पिछले कई दिनों से मौलवी अली खान पर नजर बनाए हुई थी।

गांधी कुष्ठ आश्रम में संगीत संध्या

भोपाल। वरिष्ठ समाजसेवी और सोहागपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण दास गोलानी की पुण्यतिथि पर मुस्कान और केजीएन म्यूजिकल ग्रुप ने 'हमारे पापा' कार्यक्रम का आयोजन कुष्ठ

आश्रम,गांधीनगर में किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राष्ट्रवादी विचारक शशि भाई सेठ और विधायक भगवानदास सबनानी और सुहागपुर महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कन्नू अग्रवाल ने अतिथि के रूप में हिस्सेदारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल भगवान दास सबनानी ने 'हमारे पापा' कार्यक्रम की सराहना की। मुस्कान और के जी एन म्यूजिकल ग्रुप के गायक गायिकाओं ने अनेक गीत सुनाए। कुष्ठ आश्रम के सदस्यों का मनोरंजन किया गया। उन्हें साहित्य भी भेंट किया गया। जे डी गोलानी,वर्षा गोलानी ने अतिथियों का स्वागत किया।

पहली बार दो कूबड़ वाले ऊंट समेत कई जानवर कर्तव्य पथ पर चलेंगे

5 जनवरी से मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड-2026 के टिकट, बिक्री का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकटों की बिक्री का ऐलान कर दिया है। एक बयान के मुताबिक 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी। बिक्री 14 जनवरी तक जारी रहेगी। टिकट रोज सुबह 9 बजे से तब तक खरीदे जा सकते हैं जब तक आवंटित कोटा खत्म नहीं हो जाता। टिकटों की कीमत 20 से 100 रुपए है। बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए टिकट 20 रुपए में जबकि बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की कीमत 100 रुपए है। टिकट ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। इधर, कर्तव्य पथ पर पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे। इनमें 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल हैं। ऑनलाइन टिकट के अलावा परेड के ऑफलाइन टिकट भी 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक छह काउंटर पर मिलेंगे।

ओडिशा के ढेंकनाल में खदान की चट्टान गिरी

● 2 मजदूरों की मौत,कई अब भी फंसे,ड्रिलिंग करते वक्त हुआ हादसा

ढेंकनाल (एजेंसी)। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक पत्थर की खदान में चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। पुलिस के मुताबिक हादसा शनिवार शाम को हुआ, जब गोपालपुर गांव के पास बनी खदान में कुछ मजदूर ड्रिलिंग और पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। जबकि कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे फायर सर्विस अधिकारी ने बताया कि फायर सर्विस टीमें, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, डॉग स्क्वाड और बचाव अभियान में लगी मशीनों को इलाके में भेजा गया है।

झारखंड में एसआईआर के पहले देवघर पहुंचे सीईसी

● मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के बीएलओ से करेंगे संवाद

देवघर (एजेंसी)। झारखंड में एसआईआर के पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड दौरे पर है। ज्ञानेश कुमार रविवार को अपने दो दिवसीय झारखंड प्रवास पर देवघर पहुंचे। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और

आगामी चुनावी तैयारियों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, डीआईजी अंबर लकड़ा और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पुष्पगुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। दौरे की शुरुआत आध्यात्मिक दर्शन के साथ की।

वेनेजुएला पर हमले से न्यूयॉर्क मेयर भी नाराज

अमेरिका निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करे

कराकस (एजेंसी)। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना ने उन्हें वेनेजुएला

● चीन बोला-राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है

की राजधानी काराकास से पकड़कर अमेरिका ले जाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे 'एक्ट ऑफ वॉर' बताया और कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन पर हथियार-ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। भारत की 5 वामपंथी पार्टियों (सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी) ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अगवा किए जाने की कड़ी निंदा की है। इन पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है।

कांग्रेस को तो भगवान राम के ही नाम से हो रही दिक्कत

● मोदी के फायरब्रांड मंत्री का बिहार से राहुल गांधी पर तीखा हमला

बेगूसराय (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा की जगह लागू की गई वीबी-जी राम जी योजना का विरोध करने के लिए कांग्रेस की रविवार को आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल को इस योजना में भगवान राम का नाम शामिल किए जाने के कारण आपत्ति है। गिरिराज सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेता, विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस योजना से भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह ने दावा किया, 'उन्हें (कांग्रेस को) रोजगार या समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है... उन्हें केवल भगवान राम के नाम से समस्या है।' गिरिराज सिंह ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि यूपीए सरकार के शासन के दौरान कांग्रेस ने रोजगार दिवसों को बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा था।

वीबी-जी राम जी पर बिहार से सियासी संग्राम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्व में दिए जाने वाले 100 दिन की रोजगार अवधि में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा, काम की नियमितता और आय स्थिरता में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के ग्रामीण लोगों के सशक्तीकरण और विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

देशभर में फॉरेंसिक लैब्स नेटवर्क का फैलेगा जाल

बनाने के लिए 30 हजार करोड़ निवेश करेगी सरकार,अमित शाह ने की घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में देशभर में फोरेंसिक लैब्स के नेटवर्क की स्थापना के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है। 2029 तक हर राज्य में कम से कम एक फोरेंसिक विश्वविद्यालय या केंद्रीय फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अपराध से लड़ने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) जैसे अत्याधुनिक केंद्रों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

373 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन

गृह मंत्री शाह ने शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नौ योजनाओं का उद्घाटन किया और दो योजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें 229 करोड़ रुपये का एक एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल है।

वर्तमान में देश में सात सीएफएसएल हैं

गृह मंत्री ने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकारें अगले पांच वर्षों में देशभर में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के निर्माण के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। वर्तमान में देश में सात सीएफएसएल हैं, जबकि आठ नए सीएफएसएल स्थापित किए जा रहे हैं। राज्यों के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, फोरेंसिक वैन और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। शाह ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान विभागों के मानकीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

100 यूनिट तक फ्री बिजली, 10 रुपए में ब्रेकफास्ट

● बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं का घोषणापत्र जारी

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे बंधुओं ने मुंबई की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा मुंबईकर के लिए जारी किए गए इस घोषणापत्र में टैक्स माफी का भी जिक्र है। जिसके अनुसार अब 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा। 10 रुपये में खाना और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। हर एक वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुंबई नगर निगम में खाली पदों को भरा जाएगा। वहीं शिक्षा

को लेकर इस घोषणापत्र में लिखा है कि नगर निगम के स्कूलों को बिल्डरों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। मुंबई नगर निगम बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया।

राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने की सौजन्य भेंट

राज्यपाल और मुख्यमंत्री में हुई समसामयिक विषयों पर चर्चा

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार की शाम लोक भवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को 13 दिसम्बर 2025 को सरकार के दो वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने की बधाई दी। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश शासन की उपलब्धियों पर केंद्रित पुस्तकें भेंट की और मध्यप्रदेश में बीते दो वर्षों में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी।

राज्यपाल पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2026 को 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इस की थीम 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' रखी गई है। बीता वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया था। कृषि वर्ष 2026 में आरंभ की जा रही सभी गतिविधियां अगले तीन साल का लक्ष्य तय कर संचालित की जा रही हैं। किसान कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा सभी विभागों की सहभागिता होगी। कृषि वर्ष में किसानों को अन्य राज्यों एवं विदेशों में हो रहे सफल नवाचारों की जानकारी से रू-ब-रू भी कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि विश्व

आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक 18 से 23 जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने जा रही है। इसका विषय 'ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग' और 'अनलॉकिंग न्यू सोर्सेस ऑफ ग्रोथ' है। इसमें प्रदेश में पीथमपुर जैसे ऑटो क्लस्टर्स की औद्योगिक उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और रीवा अल्ट्रा मेगासोलर प्रोजेक्ट से राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में यह योजना 'प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना' 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' के नाम से संचालित है। प्रदेश के 33 हजार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए कार्यादेश हो चुके हैं। करीब 34 हजार 600 लेटर ऑफ अवॉर्ड भी इकाइयों को प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना से प्रदेश के 52 हजार किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें देश-दुनिया के आए 120 विद्वानों के व्याख्यान, स्वामी रामभद्राचार्य महाराज भी इसमें शामिल हुए हैं। श्रीराम भक्तों ने 28 हजार से अधिक सुंदरकांड के पाठ किए। इसमें 25 सेशन होंगे, जिसमें देश-विदेश के 60 वक्ता के विचार सुनेंगे। उन्होंने बताया कि जबलपुर में ही 2 जनवरी को गीता भवन का लोकार्पण हुआ। प्रदेश का पहला गीता भवन इंदौर में लोकार्पित हो चुका है। पूरे प्रदेश मे सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जा रहे हैं जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बनेंगे। राज्यपाल श्री पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र की घटना की जानकारी भी दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, मुख्यमंत्री के सचिव श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त जनसम्पर्क श्री दीपक कुमार सक्सेना सहित लोकभवन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

आधुनिक और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान का अनूठा संगम है गीता भवन : मुख्यमंत्री

अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती की कर्मभूमि पर शुरू हुए गीता भवन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम नागरिकों में धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना के माध्यम से सामाजिक समरसता स्थापित करने प्रदेश में 'गीता भवन' बनाये जा रहे हैं। यह केन्द्र मात्र एक भवन की संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत वैचारिक अध्ययन का केन्द्र है। इनमें आधुनिकता और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के अनूठे संगम में युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, वह तेजी से पूर्ण हो रहा है। यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के पहले गीता भवन का शुभारंभ लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी इन्दौर में और दूसरा गीता भवन वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मभूमि जबलपुर में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़कर ही पुष्पित-पल्लवित होती है। गीता भवन संस्कृति को सहेजने और संवर्धित करने का बड़ा माध्यम बनेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गीता भवन राज्य की उस बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, गीता-ज्ञान और पठन-संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ना है। गीता भवन एक आधुनिक मंच है, जहाँ अध्ययन, चिंतन, शोध और सांस्कृतिक विमर्श के माध्यम से भारतीय दृष्टि को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाएगा। ये भवन अध्ययन, चिंतन और संवाद का जीवंत केंद्र बनेंगे।

गीता भवन में सुविधाएँ - गीता भवन में धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाली, साहित्यिक, प्रेरणादायी जीवनियां, और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की विविध पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में पुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठकों की सुविधा के लिए रामायण कक्ष, गीता कक्ष और सर्वधर्म पुस्तक कक्ष भी बनाए गए हैं। गीता भवन में अध्ययन के लिए आने वाले लोगों के लिये सभी सुविधाओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रवचनों और शैक्षणिक आयोजनों हेतु खूबसूरत सभागृह भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में कृष्ण को योगेश्वर श्रीकृष्ण की पहचान देने वाले चारों धामों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन, भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा का मैत्री स्थल स्वर्णगिरी पर्वत के पास ग्राम नारायणा, धार जिले का अमझेरा और रजोभूमि बदनावर जहां भगवान श्रीकृष्ण ने रात्रि विश्राम किया था। साथ ही इंदौर के पास जानापाव जहां से उन्होंने विनम्रता का संदेश दिया था। इन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है।

रेशम उत्पादन बढ़ाकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं रोजगार के अवसर : जायसवाल

प्रदेश के 3600 मलबरी एवं 850 टसर कोकून उत्पादक कृषकों को स्व-रोजगार से जोड़ा

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में रेशम का उत्पादन बढ़ाकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में रेशम संचालनालय द्वारा निजी क्षेत्र में 231 एकड़ क्षेत्र में एवं शासकीय रेशम केन्द्रों पर 200 एकड़ क्षेत्र में नवीन मलबरी पौधरोपण किया गया है। साथ ही प्रदेश के 3,600 मलबरी एवं 850 टसर कोकून उत्पादक कृषकों को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है।

राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में 2.64 लाख किलोग्राम मलबरी कोकून एवं 31.51 लाख टसर कोकून का उत्पादन किया गया। प्रदेश में 5 हजार कृषकों को नवीन कोकून उत्पादन तकनीकी से प्रशिक्षित कर उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रदेश में अभी तक 42 महिलाओं को रेशम उत्पादन से लखपति दीदी के रूप में चिन्हांकित किया गया है।

राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में मलबरी कोकून उत्पादन में वर्तमान 1.50 लाख किलोग्राम से 4 लाख किलोग्राम स्तर तक वृद्धि की जायेगी। टसर कोकून उत्पादन में वर्तमान 40 लाख से 70 लाख तक की वृद्धि का लक्ष्य है। मलबरी पौधरोपण के क्षेत्र में अतिरिक्त नवीन 3500 एकड़ की वृद्धि की जाएगी। पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम में रेशम इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रारंभ होगा। रेशम उत्पादों का विक्रय ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से प्रारंभ होगा। इसके अलावा नवीन प्राकृत शोरूम ग्वालियर, जबलपुर एवंइन्दौर में प्रारंभ होंगे।

रेशम समृद्धि कार्य-योजना- राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में 6 हजार 200 हितग्राहियों को कौशल उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्य-योजना तैयार की गई है। प्रदेश में 150 एकड़ क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण के लिए नर्सरी तैयार होगी। साथ ही 3 हजार 500 एकड़ क्षेत्र में नवीन मलबरी पौधरोपण एवं 16 नई बीज इकाइयों को प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश में 10 नई धागाकरण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। धागाकरण, बुनाई, कार्यों हेतु नवीन उन्नत मशीनों की स्थापना होगी।

संस्कृत विद्यालयों की नवीन संबद्धता एवं नवीनीकरण के लिये आवेदन आज से

भोपाल। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. द्वारा सत्र 2026-27 के लिए वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदेश के शासकीय/आदर्श संस्कृत विद्यालय/अशासकीय संस्कृत विद्यालय/शासकीय संस्कृत महाविद्यालय/परम्परागत सामान्य संस्कृत विद्यालय एवं प्राच्य आवासीय संस्कृत विद्यालय (छात्रावास युक्त) संस्कृत विद्यालयों को संस्थान से नवीन सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये अथवा सम्बद्धता नवीनीकरण के लिये सोमवार 5 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

30 जनवरी तक संबंधित शालाओं द्वारा एम.पी. ऑनलाइन पर नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण आवेदन करने के बाद 15 फरवरी 2026 तक आवेदन की हार्डकॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जाना आवश्यक है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की वेबसाइट www.mpssbhopal.org पर देख सकते है। साथ ही कार्यालयीन दिवसों में संस्थान के दूरभाष नंबर 0755-2576214, 2576215 एवं 2576209 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

भोपाल में युवक की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा

नर्स का सीपीआर देते हुए वीडियो आया सामने, डॉक्टर समेत गार्ड अस्पताल से हुए गायब

भोपाल। भोपाल के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना शनिवार देर रात की है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नर्स मृतक को रिवाइव करने के लिए सीपीआर देने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा वार्ड में ना कोई डॉक्टर व अन्य स्टाफ है। यही वीडियो परिजन ने बना कर शेयर किया है। बरखेड़ी निवासी 32 वर्षीय विशाल जोगी हबीबगंज थाना क्षेत्र स्थित अक्षय अस्पताल में भर्ती था। शनिवार शाम से उसकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। परिजनों का आरोप है कि उनके बार-बार कहने पर भी कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आया। वहीं, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह सभी आरोप गलत हैं। जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस को सूचना दी गई थी। थाने से मिली जानकारी के अनुसार, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों ने कांच-कुर्सियां तोड़ी, स्टाफ निकला

अस्पताल में हंगामे से पहले का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो विशाल के एक परिजन ने रिकॉर्ड किया है। जिसमें बेड पर लेटे मरीज को एक नर्स सीपीआर देते हुए रिवाइव करने का प्रयास कर रही है। वहीं, मौजूद परिजन अपने मरीज की स्थिति को देखते हुए रोने लगते हैं। वहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति अस्पताल में एक भी डॉक्टर ना होने का आरोप लगा रहा है। अस्पताल के स्टाफ के अनुसार, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में अचानक आ गए थे। जिन्होंने जमकर हंगामा किया। मामला बिगड़ता देख अस्पताल का स्टाफ समेत गार्ड तक मौके से खुद को बचाते हुए निकल गए थे। सिर्फ नाइट ड्यूटी वाले दो सफाई कर्मी ही अस्पताल में बचे थे। अस्पताल स्टाफ के अनुसार, विशाल की स्थिति पहले से गंभीर थी। इसकी सूचना परिजनों को पहले से थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक को बचाने का पूरा प्रयास किया था। पहले से स्थिति की जानकारी होने के बाद भी परिजन युवक की मौत के बाद आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल में लगे कांच, कुर्सियां, बोर्ड समेत अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर दी।

भोपाल में बिना टोल दिए वाहन निकालने को लेकर विवाद

विहिप और बजरंगदल पर टोलकर्मियों से मारपीट का आरोप, थाने पहुंची शिकायत

भोपाल। भोपाल के 11 मील टोल नाके पर अज्ञात युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ्री में गाड़ी क्रॉस नहीं होने दी जाने के बाद पहले एक युवक ने टोल पर हंगामा किया था। तब टोलकर्मियों ने इस युवक के साथ मारपीट कर दी थी। जिसका बदला लेने की नीयत से हंगामा मारपीट की। वीडियो फुटेज सहित मिसरोद थाने में टोलकर्मियों द्वारा शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल दोनों ही पक्षों की ओर से किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक बजरंगदल के एक पदाधिकारी शनिवार की शाम को अपनी कार के साथ 11 मील टोल पर पहुंचे। उन्होंने टोल देने से इनकार किया और कार को सर्विस लेन से निकालने का प्रयास किया। इस बात को लेकर टोलकर्मियों विरोध किया, दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हुई। तब टोल कर्मी बड़ी तादाद में एकत्र हो गए और पदाधिकारी से अभद्रता की। तब वे वहां से चले गए, कुछ देर में बड़ी तादाद में अपने साथियों के साथ टोल पर पहुंचे और डंडे से एक कर्मचारी की पिटाई की। इस विवाद का वीडियो सामने आया है। थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि टोल पर हंगामा और मारपीट का वीडियो सहित शिकायत की गई। शिकायत में किसी का नाम नहीं है। इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है कि हंगामा करने वाले बजरंगदल अथवा विहीप के कार्यकर्ता थे। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

एमपी के 29 नए अपर कलेक्टर अभी एसडीएम का काम करेंगे

5 अफसरों को सीनियर अपर कलेक्टर वेतनमान, दो डिप्टी कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर बने

भोपाल। मध्य प्रदेश को 29 नए अपर कलेक्टर एक जनवरी से मिल गए हैं लेकिन इन्हें कम से कम दो माह तक एसडीएम या कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी अधिकारी का ही काम करना होगा। 2 साल पहले अपर कलेक्टर बनने वाले सभी अधिकारियों को ही राज्य सरकार अभी तक जिलों में अपर कलेक्टर नहीं बना सकी है। अब 29 नए अधिकारियों के सामने आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को जल्दी ही इनकी पोस्टिंग का रास्ता निकालना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर को आदेश जारी कर एक जनवरी 2026 से 29 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रमोट किया है। इन अधिकारियों की अच्छी सीआर के आधार पर इन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (संयुक्त कलेक्टर) से प्रवर श्रेणी वेतनमान (अपर कलेक्टर) देने का आदेश जारी किया गया है। 12 दिसम्बर 2025 को हुई विभागीय चयन समिति की बैठक के बाद क्रमोन्नत किए गए इन अधिकारियों की पोस्टिंग अभी जिलों में एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर के रूप में है। इन्हें अब जिलों में अपर कलेक्टर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पद पद पदस्थ किया जाएगा क्योंकि दोनों ही पद समान वेतनमान और अधिकार वाले हैं। जो अन्य संयुक्त कलेक्टर अपर कलेक्टर पद पर प्रमोट हुए हैं उनमें रविशंकर राय भोपाल, बृजेन्द्र कुमार रावत नर्मदापुरम, लक्ष्मीकांत खरे भोपाल, मकसूद

अहमद बैतूल, बृजेश सक्सेना उज्जैन, विनय द्विवेदी उपायुक्त राजस्व सागर संभाग, हुनेंद्र घोरमारे, मायाराम कौल बालाघाट, हेमलता सोलंकी खरगोन, ज्योति भलावे छिंदवाड़ा, दिनेश सिंह तोमर सीहोर, वीरेंद्र सिंह दांगी राजगढ़, अयोध्या प्रसाद द्विवेदी मऊगंज, राजेश कुमार यादव उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल, जमील खान सीहोर, ममता खेड़े उपसंचालक प्रशासन अकादमी, विनीत तिवारी भोपाल के पद पर पदस्थ हैं। विभाग ने कहा है कि चार संयुक्त कलेक्टर अयोध्या प्रसाद द्विवेदी, राजेश कुमार यादव, जमील खान, ममता खेड़े, विनीत तिवारी को उनसे सीनियर अफसरों की जांच के चलते रहने और प्रमोशन का लिफाफा बंद रखने के चलते प्रमोट किया गया है। अगर सीनियर अफसरों की जांच खत्म हो जाती है और क्लीनचिट मिलती है तो अपर कलेक्टर के पद पर प्रमोट हो चुके अंतिम पांच अफसरों को क्रमावनत किया जाएगा।

दो डिप्टी कलेक्टर बने संयुक्त कलेक्टर

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में दो डिप्टी कलेक्टरों को प्रमोट कर संयुक्त कलेक्टर बनाया है। ये अधिकारी राकेश परमार डिप्टी कलेक्टर इंदौर और अनुराग निंगवाल डिप्टी कलेक्टर शिवपुरी हैं। इसके अलावा अपर कलेक्टर स्तर को पांच अफसरों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पर क्रमोन्नत किया है। सीनियर अपर कलेक्टर की कैटेगरी में आने वाले ये अधिकारी महिप कुमार तेजस्वी उप सचिव सामान्य प्रशासन पूल, लक्ष्मी गामड़ अपर नियंत्रक गवर्नमेंट प्रेस भोपाल, प्रवीण फुलपगारे सीईओ जिला पंचायत दमोह, भुरला सोलंकी अपर कलेक्टर शाजापुर और महेंद्र सिंह कवचे अपर कलेक्टर दतिया हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मसूरी में संदिग्ध हालत में मौत

- **भोपाल से अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया था**
- **बर्थडे सेलीब्रेशन के बाद सोया, सुबह बिस्तर में मृत मिला**

भोपाल। भोपाल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों के साथ नए साल की छुट्टियां मनाने मसूरी गए था। जहां संदिग्ध हालात में मौत हो गई।

शुक्रवार रात जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के बाद युवक अपने कमरे में सोने गया था। शनिवार सुबह वह कमरे में बेसुध हालत में मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्ट्म के लिए मॉर्चुरी में रखवा दिया है। मौत के कारणों का खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगा। मौत की सूचना शनिवार सुबह करीब 11 बजे एमडीटी-112 के जरिए पुलिस को मिली थी। पुलिस के अनुसार, हर्ष 1 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ मसूरी पहुंचा था। 2 जनवरी की रात दोस्तों ने साथी भावना वर्मा का जन्मदिन मनाया। पार्टी के बाद रात करीब 11 बजे हर्ष अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह कमरे में मृत मिला।

संपादकीय

गिग वर्करों को वर्कर तो मानें

बेशक देश भर में हुई, उस हड़ताल की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक नए किस्म के कामगारों की मानवीय और श्रम अधिकारों को लेकर उसने देश का ध्यान खींचा। यह हड़ताल उन हजारों गिग कर्मचारियों की थी, जिन्हें आमतौर पर लोग डिलीवरी ब्वॉय या कैब ड्राइवर के रूप में जानते हैं। लोग इनका बेसब्री से इंतजार तो करते हैं, लेकिन उनकी कठिन जिंदगी के बारे में नहीं जानना चाहते। ये गिग कर्मचारी ब्लिंकिट, जोमाटो, स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करते हैं, जिनका दावा है कि वो 10 मिनट में ग्राहक तक मनचाहा सामान पहुंचाती हैं और जिनके कारण लोग और ज्यादा आलसी हो गए हैं। गिग वर्कर्स यूनियनों ने बेहतर वेतन, सुरक्षित काम करने की जगहें और सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग करते हुए हड़ताल का आह्वान किया था। उन्होंने 10 मिनट की डिलीवरी पर भी रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना है कि डिलीवरी का समय पूरा करने के लिए तेज़ी से भागने से राइडर्स की जान खतरे में पड़ती है। भुगतान प्रणाली को लेकर भी यूनियन का कहना है कि कंपनियां पीक ऑवर्स में ज्यादा रेट दिखाकर कर्मचारियों को आकर्षित करती हैं, जिससे कर्मियों की संख्या बढ़ जाती है और प्रति कर्मचारी कुल भुगतान कम हो जाता है। भर्ती पर कोई सीमा न होने और एल्गोरिदम आधारित फैसलों के ज़रिए 'अनुचित श्रम व्यवहार' (अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज) अपनाने के आरोप भी लगाए गए हैं। कंपनियां तो यह मानने को तैयार ही नहीं है कि गिग वर्कर्स का शोषण हो रहा है। वो इन्हें वर्कर के बजाए डिलीवरी पार्टनर कहती हैं। जब कि गिग वर्कर्स यूनियनों का दावा है कि हड़ताल में 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी राइडर्स ने भाग लिया। हालांकि हड़ताल के आव्हान के मद्देनजर कंपनियों ने वैकल्पिक वैसे व्यवस्था कर ली थी। ब्लिंकिट का दावा है नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अब तक के सबसे ज्यादा 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए। बहरहाल इस एक दिनी हड़ताल के बाद सरकार ने 31 दिसंबर को एक मसौदा जारी किया। इस पर हित धारकों के सुझाव मांगे गए हैं। इसके तहत गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा। यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इसके तहत सरकार का इरादा जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत तमाम प्लेटफॉर्म के डिलीवरी ब्वॉटयज, ओला-उबर कैब ड्राइवर को सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहता है। इसके लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बनाए गए ड्राफ्ट में प्रस्तावित किया है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 समेत चार नए लेबर कोड्स 21 नवंबर, 2025 को नोटिफाई किए गए थे। हालांकि इसका लाभ कितने लोगों को मिल सकेगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि सरकार ने इसमें यह शर्त भी जोड़ दी है कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ केवल उन्हें गिग वर्कर्स को मिलेगा, जो एक कंपनी के साथ साल में कम से कम 90 दिन कर चुका हो। अगर इस अवधि में वह एक से अधिक ऐप या कंपनियों के साथ काम करता है, तो कुल मिलाकर उसे न्यूनतम 120 दिन काम करना होगा। यहां पेंच यह है कि कोई भी कंपनी 90 दिन पूरे होने से पहले ही गिग वर्कर को शंट कर देगी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने एक दिन के काम की व्याख्या कर दी है। इसके मुताबिक किसी दिन चाहे जितनी भी कमाई हुई हो, यदि उस दिन काम किया गया है तो उसे एक कार्यदिवस माना जाएगा। लेकिन गिग वर्करों की यह लड़ाई अभी लंबी है।

विदेश नीति के कठिन दौर में एकजुटता जरूरी

नजरिया

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी विचारक हैं।

भारत के प्रधानमंत्री भी सामान्य राजनायिक शिष्टाचार की परंपराओं को तोड़कर स्वयं हवाई अड्डे पर श्री पुतिन को लेने गए और साथ-साथ कार में आए। मात्र 24 घंटे में तीन मुलाकातें हुईं। यह मुलाकातें (खाने के अलावा) पहले-रात्रि भोज प्रधानमंत्री जी के निवास पर था जो बहुत सीमित था यहां तक कि उसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी नहीं थे, एकदम वन-टू-वन चर्चा। दूसरा भोज राष्ट्रपति भवन में था। यह कुछ ज्यादा खुला था। यानी इसमें कुछ ज्यादा लोग निमंत्रित थे। उम्मीद थी कि कुछ बड़े निर्णय पुतिन के इस दौरे में जो 4 वर्ष के बाद हुआ था, हो सकेंगे। परंतु यात्रा समाप्ति के बाद 6 व 7 दिसंबर के अखबारों या मीडिया में कोई विशेष चर्चा उनकी यात्रा की नहीं हुई।

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पूरी हो गई है, वे रुस वापस लौट चुके हैं। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि पुतिन की यात्रा के कई दिन पहले भारतीय मीडिया में भारी प्रमुखता से जो समाचार पुतिन को लेकर आ रहे थे और आकर्षक वातावरण बनाया जा रहा था, लगभग सारा मीडिया पुतिन की यात्रा को एक महान घटना बताने के लिए बेचैन था यहां तक कि उनकी कार कैसी है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? आदि-आदि मीडिया में समाचार छप रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री भी सामान्य राजनायिक शिष्टाचार की परंपराओं को तोड़कर स्वयं हवाई अड्डे पर श्री पुतिन को लेने गए और साथ-साथ कार में आए। मात्र 24 घंटे में तीन मुलाकातें हुईं। यह मुलाकातें (खाने के अलावा) पहले-रात्रि भोज प्रधानमंत्री जी के निवास पर था जो बहुत सीमित था यहां तक कि उसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी नहीं थे, एकदम वन-टू-वन चर्चा। दूसरा भोज राष्ट्रपति भवन में था। यह कुछ ज्यादा खुला था। यानी इसमें कुछ ज्यादा लोग निमंत्रित थे। उम्मीद थी कि कुछ बड़े निर्णय पुतिन के इस दौरे में जो 4 वर्ष के बाद हुआ था, हो सकेंगे। परंतु यात्रा समाप्ति के बाद 6 व 7 दिसंबर के अखबारों या मीडिया में कोई विशेष चर्चा उनकी यात्रा की नहीं हुई। यानी ऐसा कुछ लगा कि जिस उत्साह या विश्वास से यात्रा की चर्चा हुई थी वैसे अनुकूल परिणाम बातचीत के बाद नहीं निकल सके। इसलिए यात्रा के बाद मीडिया का आधा हिस्सा शांत रहा और या फिर शेष कुछ सरकारी विज्ञप्तियों तक सीमित रहा। श्री पुतिन की यात्रा के पहले एक प्रारंभिक वातावरण बनाने के लिए इस बार देश के दो चर्चित पत्रकार जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत नजदीक माना जाता है, अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन जो इंडिया टुडे का विदेश विभाग देखते हैं, को मास्को भेजा गया था। मेरी स्मृति में यह पहली बार हुआ है कि जब यात्रा और बातचीत का आधार तय करने के लिए पत्रकारों को भेजा गया हो। श्री पुतिन से दिल्ली के पत्रकारों का साक्षात्कार मास्को में तय होना यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जो पुतिन अपने ही देश के पत्रकारों से नहीं मिलते, बल्कि उनके बयान और समाचार पहुंचा दिए जाते हैं, वे भारतीय पत्रकारों को साक्षात्कार मास्को में बुलाकर देंगे या भारतीय पत्रकार मास्को जाकर साक्षात्कार लेने की अनुमति मिल जाएगी यह आसान नहीं है। मतलब साफहै कि सरकार ने अपनी ओर से जमीनी आधार तैयार करने के लिये (बातचीत के लिए) इन पत्रकारों को पहुंचाया था। जब कोई विदेशी मेहमान (सत्ता प्रमुख) भारत आता है तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या कोई रक्षा मंत्री बातचीत करते हैं और सत्ता के प्रमुखों की बैठक के लिये आधार भूमि तय करते थे। दोनों तरफके मुखियाओं के विचार विनिमय के लिए आधार बिंदु तैयार करते है।

श्री पुतिन और श्री मोदी के बीच बताया जाता है कि 16 करार हुए हैं, परंतु इनमें भी कोई ठोस मुद्दे या बिंदु नजर नहीं आए जिनका निर्णायक हल होने की उम्मीद थी। श्हम आतंकवाद के खिलाफहैंय या श्एकजुट हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं,य श्आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगेय आदि ऐसे शाब्दिक जुमले हैं जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता। रात्रि भोज, निजी भोज फोटो सेशन यह सब तो एक समान्य शिष्टाचार की सीमाओं में आते हैं। इन्हें प्रचारित करना मीडिया के लिए क्यों जरूरी है? इसे सब जानते हैं। मीडिया का यह भी कहना है कि भारत-रूस के पुराने संबंध हैं, रूसी जनता में भारतीयों के प्रति बहुत प्रेम हैं या भारतीय जनता के मन में रूस के प्रति प्रेम हैय यह सब शिष्टाचार के जुमले हैं।

भारत आने से पहले पुतिन का बयान आया था कि वे 10 लाख भारतीय लोगों को रूस में रोजगार देंगे। उनके जाने के बाद की सरकारी विज्ञप्तियों में इस बारे में कोई अधिकृत घोषणा नहीं है। इतना अवश्य छपा है कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा कि जो भारतीय रुसी सेना में हैं उन्हें शीघ्र वापस भेजा जाए। पुतिन ने इस पर सहमति जताई, यद्यपि कोई समय सीमा की बात दोनों पक्षों ने नहीं की। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह जो लोग रुसी सेना में भर्ती हैं, इन्हें सेना में भर्ती के लिये ले जाया गया था या उन्हें रोजगार के नाम पर ले जाकर बलात् रुसी सेना में यूक्रेन से लड़ने के लिए भर्ती कर दिया गया था। पिछले दिनों ऐसी खबरें भारतीय मीडिया में आई थीं। कई लोगों ने यह शिकायत की थी कि उनके बच्चों को नौकरी के नाम से धोखे से ले जाकर सेना में भर्ती कर दिया गया। इसकी भी कोई प्रमाणिक जानकारी अभी तक भारतीय सरकार ने नहीं दी कि कितने लोग रूस में रोजगार के लिए गए थे, उनमें से कितने लोग सेना में भर्ती किए गए। क्या वह अभी भी सेना में रहना चाहते हैं या नहीं आदि-आदि। ऐसा लगता है कि शायद राष्ट्रपति पुतिन 10 लाख लोगों को रोजगार के नाम पर रुसी सेना में भर्ती करना चाहते होंगे, क्योंकि लंबे समय से यूक्रेन-रूस युद्ध में हजारों सैनिकों की मौतों के बाद दोनों पक्षों के पास सैनिकों का अभाव है। रूस के पास अपने हथियार हैं, यूक्रेन के पास नाटो और अमेरिकी हथियार हैं। परंतु हथियार स्वतरू तो नहीं लड़ सकते। हथियार को लड़ने वाला एक इंसान चाहिए। यूक्रेन के लिए कुछ सैनिकों का सहयोग नाटो से प्राप्त हो रहा है और रूस के सामने संकट है। भारत के प्रधानमंत्री भी प्रत्यक्ष तौर पर सेना में भर्ती के रोजगार के लिए भारतीयों को भेजने का कोई समझौता नहीं कर सकते थे। अगर वह ऐसा करते तो उन्हें देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ता। भारत ने भी रूसी लोगों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई-पर्यटक वीजा तथा समूह पर्यटक वीजा देने की घोषणा की है परंतु यह भी सामान्य सी बातें हैं।

इन 16 समझौतों में जो अन्य समझौते हुए हैं, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सहयोग, उर्वरक, शैक्षिक, मीडिया के सहयोग के करार शामिल हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि यह जो 16 करार हुए हैं, यह कोई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं है। पुतिन का यह कहना है कि दोनों पक्ष वार्षिक व्यापार को वर्तमान 64 अरब अमेरिकी डॉलर से 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने पर विचार कर रहे हैं, हालांकि यह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जिस प्रकार से दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत घट रही है। 6 दिसंबर 25 को 1 डालर के बराबर 90 रुपये हो चुके हैं। अगर इसके आगामी 5 वर्ष के संभावित आंकड़ों को निकाला जाए तो यह व्यापार वृद्धि नगण्य ही मानी जाएगी। वैसे भी समझौते में जिन बीजों का व्यापार या आदान-प्रदान का निर्णय हुआ है, क्या वह भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई उल्लेखनीय माना जा सकता है? भारत रूस से तेल का पुराना ग्राहक है और वह कम या ज्यादा अभी भी रहेगा। प्राकृतिक गैस, कोयला, उर्वरक धातु आदि आज के दौर की ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जिन्हें भारत रूस से आयात करता है और बदले में भारत रूस को ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग, गुड्स टेक्सटाइल्स, कृषि व समुद्री उत्पाद यानी मछली आदि भेज सकता है। यह सब कोई बुनियादी जरूरतें नहीं है।

दरअसल पुतिन के आने के पहले यह प्रचारित किया गया कि भारत-रूस के बीच कोई बड़ा हथियार समझौता हो सकता है। विशेषतरूमिसाइल 400 का जो भारत के लिए सीमा की रक्षा के लिए जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी रूसी मिसाइल की सफलता सिद्ध हो चुकी है। परंतु इस संबंध में कोई ठोस समझौते की रपट कम से कम मीडिया में तो नहीं आई। अभी यह भी कहा जा रहा है कि श्री पुतिन से ब्लोदिवोस्तोक कॉरिडोर से सामान लाने और भेजने की चर्चा हुई है। भारत-रूस पारंपरिक मार्ग जो मुंबई से स्वेज नहर होकर सेंट पीटर्सवर्ग को जाता है, उसकी लंबाई 16 हजार किलोमीटर की तुलना में यह कॉरीडोर लगभग 6 हजार किलोमीटर कम होगा। यानी लगभग 10 हजार किलोमीटर की लंबाई होगी। परंतु क्या यह अभी इतनी आसानी से संभव है? क्योंकि यह मार्ग दक्षिण चीन सागर और जापान सागर से होकर जाएगा। क्या इसके लिए चीन सहमति देगा? जो चीन, यूरोप और ईरान को जोड़ने के लिए वन रोड वन बेल्ट की सड़क योजना बना रहा है, क्या वह इसे होने देगा? क्या यह मार्ग सुरक्षित होगा? कुल मिलाकर यह समुद्री कॉरिडोर बनाने की समझ भी कोई महत्वपूर्ण समझौता नजर नहीं आती। चीन जिस प्रकार से पिछले दिनों सीमा के प्रश्न को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है अरुणाचल को भारतीय सीमा मानने को तैयार नहीं है तो क्या वह भारत के व्यापार के लिए आसानी से मार्ग खोल देगा? यह कल्पना कम से कम मुझे ठोस नजर नहीं आती।

ऐसा लगता है कि अमेरिका से संबंध में तनाव आने के बाद भारत की सरकार भटकाव में है। और यह भारतीय राजनीति का दुखद पक्ष है कि श्री पुतिन की यात्रा के बाद संसद का जो सत्र शुरू हुआ, उसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी ने भी इन बुनियादी राष्ट्रीय चिताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। प्रतिपक्ष की चिंता है कि नेता प्रतिपक्ष को पुतिन से क्यों नहीं मिलाया और सत्ता पक्ष का उत्तर है कि यह सरकार का दायित्व नहीं है। पुतिन या कोई विदेशी मेहमान किस से मिलना चाहते हैं इसका फैसला वही करेंगे। हालांकि अच्छा होता कि विदेश नीति के इस कठिन दौर में भारत सरकार राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय देती और किसी एक संवैधानिक पदाधिकारी के भोज में प्रतिपक्ष के नेता को मिलाते या एक औपचारिक या अनौपचारिक बैठक का आयोजन कर सकती थी जो समूची भारत की संसद का लघु रूप होता और राष्ट्रीय एकजुटता का भी पर्याय होता। परंतु ऐसा लगता है कि श्री पुतिन और श्री मोदी में आत्मिक समानता है। पुतिन भी रूस में किसी विपक्ष या समकक्ष के साथ विचार विमर्श में विश्वास नहीं करते और यही शैली भारत में श्री नरेंद्र मोदी की भी है!

न्यायाधीश पर महाभियोग की कोशिश डरावनी

मुद्दा

अवधेश कुमार
लेखक पत्रकार हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध विपक्ष द्वारा पिछले संसद सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल अभूतपूर्व और अचंभित करने वाली थी। किसी न्यायाधीश को उसके न्यायिक निर्णय या आदेश के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए हमारे माननीय सांसद इस तरह एकजुट हो जाएंगे इसकी कल्पना नहीं थी। हालांकि इसके विरुद्ध 56 पूर्व न्यायाधीश सामने आ गए जिन्होंने खुला पत्र में इसे न्यायालय पर राजनीतिक वैचारिक दबाव बनाने और डराने की कोशिश कहा। वास्तव में तमिलनाडु में आईएनडीआईए सरकार का नेतृत्व करने वाली द्रमुक के आह्वान पर एक साथ 107 सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की घटना हर दृष्टि से असाधारण थी। अभी तक न्यायाधीशों को उनके आचरण, कदाचार आदि के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा या उसकी कोशिशें हुईं। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा है कि सांसदों के आरोप मान लिए जाएं, तब भी किसी न्यायाधीश को उसके विचारों या फैसलों के आधार पर महाभियोग की धमकी देना न्यायपालिका की आजादी पर हमला है। अगर इस तरह किसी सरकार राजनीतिक दल या दलों के समूह को न्यायाधीश का फैसला स्वीकार नहीं हो और वह महाभियोग प्रस्ताव लाने लगे तो फिर हर न्यायाधीश डरने लगेगा। वास्तव में इस प्रकरण के तीन प्रमुख पहलू है। पहला, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा दिया गया फैसला और उसकी पृष्ठभूमि। दूसरा, संबंधित विवाद की सच्चाई। और तीसरा महाभियोग प्रस्ताव के पीछे की सोच या विचारधारा।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तिरुप्परनकुंद्रम मंदिर पर परंपरागत उत्सव के दीप जलाने का एक आदेश 1 दिसंबर को दिया तथा प्रशासन द्वारा उसका पालन न करने पर तीखे शब्दों में दूसरा आदेश 4 दिसंबर को दिया। न्यायालय ने 4 दिसंबर के आदेश में इसे न्यायपालिका की अवमानना करार देते हुए हर हाल में लागू करने की बात की। द्रमुक सरकार ने इसे सांप्रदायिक निर्णय माना और उनके विरुद्ध राजनीतिक अभियान चल निकला है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल,तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से संबंधित पत्थर स्तंभ- दीपथून पर दीपक जलाकर कार्तिगई दीपम त्योहार मनाने की परंपरा है। तमिल महीने कार्तिगई (नवंबर-दिसंबर) में मनाए जाने वाले 'कार्तिगई दीपम' उत्सव के तहत, हमेशा की तरह उच्ची पिल्लैयार मंदिर के मंडपम में दीप जलाने के लिए जब लोग जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। तिथि के अनुसार 3 दिसंबर को दीप जलाया जाना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद यह बड़ा मुद्दा बन गया और न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका डाली गई जिसके तहत यह आदेश आया। मंदिर और पहाड़ी की सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के साथ जब श्रद्धालु दीपक जलाने जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें फिर रोक दिया। तीरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर से 10 किमी दूर है जिस पर यह मंदिर अवस्थित है। सनातन और हिंदू मान्यताओं में यह भगवान मुरूगन या कार्तिकेय के छः निवास स्थानों में से एक है। मुरूगन भक्तों के लिए इसके महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। विवाद का मुख्य कारण पहाड़ी के ऊपरी भाग पर स्थित सिकंदर वधुसाह का दरगाह है। जैसा हम जानते हैं तमिलनाडु वैष्णव और शैव दोनों पंथों का आधार और मुख्य विस्तार भूमि रहा है। वैष्णव परंपरा के कवि और संत 12 अलवरों तथा 63 नयनारों यानी शैश परंपरा के कवियों और संतों में से अधिकांश तमिल क्षेत्र से आए थे। मंदिर समर्थकों की मान्यता है कि यह पूरी पहाड़ी शिवलिंग है जिसके बीच में भगवान मुरूगन का मंदिर है। यह सच है कि जब दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य यहां तक फैला उसके बाद से समस्या शुरू हुई। सिकंदर वधुशाह का दरगाह 17वीं शताब्दी में बना था जबकि मंदिर का उल्लेख छठी शताब्दी तक मिलता है। विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को पराजित कर मंदिर और वहां की परंपरा को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पुनर्स्थापित किया। बाद में समस्या फिर बढ़ी और अंग्रेजों के काल में इसे लेकर लगातार विवाद होते रहे। न्यायालय के कुछ फैसले भी हैं जिनमें 1920 के एक आदेश का न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने उदाहरण भी दिया है।

द्रमुक के संस्थापक ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार की पूरी सोच सनातन या हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। अपने पिछले कुछ सालों में द्रमुक नेताओं द्वारा सनातन को वारस से लेकर डेंगू मलेरिया अधिक कहकर निंदा करने और इसके हर हाल में विरोध के जो स्वर सुने जा रहे हैं वो इसी विचारधारा से निकली है। द्रमुक की राजनीति इस हिंदू धर्म के विरोध पर टिकी है जिसे कुछ लोग नास्तिकतावाद भी कहते हैं। हालांकि विडंबना देखिए कि उसे नास्तिकतावाद में इस्लाम या ईसाइयत का विरोध नहीं है। जब पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद लंबे कालखंड से पड़े ऐसे अनेक विवाद अनसुलझे रह गए तो फिर तमिलनाडु में इसके सुलझाने की संभावना ही नहीं थी। द्रमुक सरकार हिंदू संगठनों के विरुद्ध कितना आक्रामक रहती है एवं उनके कार्यक्रमों तक को रोकने के कदम उठाए जाते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं।

किंतु धीरे-धीरे तमिलनाडु में इसके विरुद्ध संगठन और समूह खड़े हुए जो मुखर होकर सामने आने लगे हैं। तिरुप्परकुंदरम विवाद पिछले दिनों तब ज्यादा गहराया जब कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे सिकंदर मलाई पहाड़ी नाम देने की मांग कर आंदोलन शुरू किया। कुर्बानी की कोशिश हुई जिसका विरोध हुआ। इन कारणों से वहां तनाव की स्थिति बनी या जानबूझकर बनायी गयी और मंदिर के सामान्य पूजा पाठ को छोड़ अन्य गतिविधियों को प्रशासन ने लगभग रोक दिया। ऐसा नहीं होता तो कार्तिकेय दीपम के लिए न्यायालय जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। दक्षिण में भगवान मुरूगन सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवताओं में है और इनको मानने वाले में समाज के पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा है।

पूरे विवाद को निष्पक्षता से देखने के बाद आप अपना निष्कर्ष निकालिए। किंतु मान लीजिए कोई सरकार या पार्टी न्यायाधीश के फैसले से असहमत है तो उसका रास्ता महाभियोग होगा? उच्च न्यायालय की एकल पीठ के विरुद्ध बड़ी पीठ में जाया जा सकता था। आपके लिए उच्चतम न्यायालय का रास्ता खुला है। ऐसा लगता है कि चूंकि तमिलनाडु सरकार को सच मालूम है इसलिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डालने की जगह ऐसा दबाव बनाओ ताकि आगे इस तरह के फैसले देने से डरे। 56 न्यायाधीशों ने अपने पत्र में लिखा है कि आपातकाल में भी न्यायाधीश राजनीतिक आसहमति के कारण निशाने पर आए थे और तब भी न्यायपालिका ने स्वतंत्रता की रक्षा बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वस्तुतः महाभियोग न्यायपालिका की ईमानदारी की रक्षा करने के लिए है, न कि जजों पर दबाव डालने या बदला लेने के लिए इस्तेमाल करने। हाल के वर्षों में कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एसए बोबडे और डीवाई चंद्रचूड़ साथ ही वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी निशाना बनना पड़ा क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं को उनके फैसले पसंद नहीं आए। महाभियोग और सार्वजनिक आलोचना को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सेकुलरिज्म के नाम पर सरकार और प्रशासन के लंबे समय से जारी ऐसे रवैयों के विरुद्ध पूरे देश और देश के बाहर हिंदुओं के अंदर गुस्सा और प्रतिक्रिया का भाव चरम तक पहुंचा है जिसकी कई परिणति हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मानने लगे हैं कि सेक्युलरवाद के नाम पर हिंदू और सनातन विरोध तथा मुस्लिमपरस्ती राजनीतिक दलों और सरकारों का चरित्र है। भाजपा के अलावा कोई राजनीतिक दल समर्थन में नहीं आता इसलिए इस गुस्से का लाभ सीधे तौर पर उसे मिलता है। द्रमुक का संकीर्ण एकपक्षीय तमिलवाद व हिंदू धर्म विरोधवाद की अपनी राजनीति है लेकिन कांग्रेस, सपा, तृणमूल आदि का भाजपा विरोध के नाम पर उनके साथ आना आने वाले समय में राजनीतिक रूप से इनके लिए और प्रतिकूल साबित हो सकता है।

कर्तव्य की कसौटी पर ईमानदारी

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

ईमानदारी को प्रायः हम बड़े नैतिक आदर्शों, सच बोलने या धोखा न देने तक सीमित मान लेते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में ईमानदारी का सबसे सशक्त और व्यावहारिक रूप तब दिखाई देता है, जब व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सच्चा, जिम्मेदार और निष्ठावान होता है। वास्तव में, अपने काम के प्रति ईमानदारी ही असली ईमानदारी है, क्योंकि यही वह मजबूत आधार है जिस पर व्यक्ति का चरित्र, समाज की व्यवस्था और राष्ट्र की प्रगति टिकी होती है।

अपने कार्य के प्रति ईमानदार होने का अर्थ है।अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा, परिश्रम और सत्यनिष्ठा के साथ निभाना। चाहे व्यक्ति विद्यार्थी हो, शिक्षक, किसान, मजदूर, डॉक्टर, अधिकारी या व्यापारी यदि वह अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है, तो वह न केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, बल्कि समाज के प्रति भी अपना दायित्व निभाता है। उदाहरणस्वरूप, एक विद्यार्थी यदि मन लगाकर अध्ययन करता है, नकल का सहारा नहीं लेता और ज्ञान प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बनाता है, तो वह अपने कार्य के प्रति ईमानदार कहलाता है।

यही ईमानदारी आगे चलकर उसे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। आज के समय में ईमानदारी का अभाव केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्य के प्रति लापरवाही भी एक प्रकार की बेईमानी है। समय पर कार्य न करना, जिम्मेदारी से बचना, अधूरा या दिखावटी काम करना। ये सभी अपने कर्तव्यों के प्रति असत्यनिष्ठा के उदाहरण हैं। यदि एक डॉक्टर मरीज को केवल औपचारिक रूप से देखे, शिक्षक पूरे मन से पढ़ाने के स्थान पर केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित रह जाए या अधिकारी अपने कर्तव्यों को टालता रहे, तो इसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसलिए ईमानदारी का वास्तविक मूल्य तभी है, जब वह हमारे दैनिक कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

अपने काम के प्रति ईमानदारी व्यक्ति को आत्मसंतोष प्रदान करती है। जब हम जानते हैं कि हमने अपना कार्य पूरी सच्चाई और मेहनत से किया है, तब मन में किसी प्रकार का अपराधबोध नहीं रहता। यही आत्मसंतोष मानसिक शांति का स्रोत बनता है। भले ही धन, पद या प्रशंसा तुरंत न मिले, पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अवश्य बढ़ता है। यही आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इतिहास और समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ साधारण व्यक्तियों ने अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से असाधारण परिवर्तन किए। एक सफाईकर्मी यदि प्रतिदिन पूरे मन से अपना कार्य करता है, तो वह शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी प्रकार, एक किसान यदि ईमानदारी से खेती करता है, तो वह देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है। ये कार्य देखने में भले ही छोटे लगें, परंतु इनके बिना समाज की कल्पना भी संभव नहीं है।

इससे स्पष्ट होता है कि काम की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही ईमानदारी को परिभाषित करता है। जब व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है, तो समाज में विश्वास का वातावरण बनता है। लोग एक-दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं, जिससे सहयोग, आपसी सम्मान और सामूहिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत, जब लोग केवल स्वार्थ या निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं, तो व्यवस्था कमजोर हो जाती है और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि समाज की एक आवश्यक शर्त है।

आज के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, परंतु यह मार्ग क्षणिक लाभ तो दे सकता है, स्थायी सफलता नहीं। दीर्घकाल में वही व्यक्ति सफल और सम्मानित होता है, जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा, धैर्य और ईमानदारी से करता है।

सच्ची सफलता वही है, जो परिश्रम और सत्यनिष्ठा के मार्ग से प्राप्त हो। अंततः कहा जा सकता है कि ईमानदारी कोई दिखावटी आभूषण नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सशक्त कार्यशैली है। अपने काम के प्रति ईमानदार होना ही असली ईमानदारी है, क्योंकि यही हमारे व्यक्तित्व और चरित्र की वास्तविक पहचान बनती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का कार्य पूरी निष्ठा से करे, तो न केवल उसका स्वयं का जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज और राष्ट्र भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। निश्चय ही, ईमानदारी से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े परिवर्तन की नींव रख सकता है और यही इस विचार की सबसे बड़ी सार्थकता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

गर्व करने वाले लोग

व्यंग्य

सुधीर नायक
लेखक व्यंग्यकार हैं।

कल कुछ लोग मिले। मैं पूछ बैठा-भाई, आप लोग क्या करते हैं?

वे बोले-हम गर्व करते हैं।हम गर्व करने वाले लोग हैं।

मैंने कहा-वो तो ठीक है,पर आप लोग काम क्या करते हैं? गर्व करने के अलावा कुछ काम भी तो करते होंगे न।

वे बोले-हम गर्व करते हैं और क्या? जो गर्व करता है वो फिर कुछ और थोड़े करता है। करने वाले करते हैं। हम तो बस उसपर गर्व करते हैं। आखिर गर्व करने वाले भी चाहिए कि नहीं। हम वही लोग है।हमारे देश की गर्व करने लायक कितनी सारी चीजें हैं। पुरानी भी हैं,नयी भी हैं। अब आप सोचिए, सिंधु घाटी से आज तक कितना लंबा टाइम है। ढ़ेरों चीजें हैं।जीवन निकल जायेगा गर्व करते करते। हमें तो गर्व करने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती।पता नहीं लोग दूसरे कामों को कैसे टाइम निकाल लेते हैं। आप अजीब आदमी हैं। आप हमसे कुछ और करने के लिए कहते हैं। गर्व करना फुल टाइम जॉब है,भाई। गर्व करने के बाद और कुछ करने की गुंजाइश नहीं बचती। हम और कुछ करने लगेंगे तो गर्व कब करेंगे। गर्व करना आसान नहीं है। गर्व वाली चीजें ढूंढ़ो। फिर उन्हें छानो। उनमें बिना गर्व वाला कुछ हो तो उसे अलग करना पड़ता है। फिर गर्व की तैयारी में बहुत समय लगता है। गर्व कब करना है,कैसे करना है,कितना करना है, कहां करना है,किसके सामने करना है? सारी रुपरेखा तैयार होती है। ऐसा थोड़े ही है कि मुंह उठाया और गर्व करने पहुंच गए। जैसे हमें आज ही पता चला है कि जर्मनी में संस्कृत पढ़ने का बड़ा क्रेज़ है।वहां 14 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। हम इस पर गर्व करेंगे। फिजी में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। इस पर गर्व करने की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में अमेरिका जैसे देशों के समकक्ष पहुंच रहा है।ये सब हमारे एजेंडे में है। इन सब पर गर्व की तैयारी है।

मैंने टोका-लेकिन आप तो संस्कृत नहीं सीखते। आप हिंदी में काम भी नहीं करते। राष्ट्र की प्रगति में भी आपका कोई योगदान नहीं दिखता। फिर दूसरों के किये हुए पर गर्व का क्या मतलब? आप सोने की चिड़िया में खोये रहे और आपके आंगन की चिड़िया गायब हो गयी।

वे लोग झल्ला पड़े-हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आपको गर्व नहीं है। आप हमारी बिरादरी के नहीं हैं। हम केवल गर्व करने वालों से मतलब रखते हैं।आप जाइए यहां से।

मैं फिर भी अड़ा रहा। मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा-भाई, गर्व करना अच्छी बात है। लेकिन गर्व लायक हम भी तो कुछ करें। मेरे दादा जी हाथी पालते थे तो कम से कम मैं बकरी तो पालूं। मेरे भाई के घर में मोर है तो मेरे घर में कबूतर तो हो। दादा जी के हाथी के किस्से कब तक सुनाता रहूंगा। भाई के मोर का कब तक बखान करूंगा।

वे लोग नाराज़ हो गए।वे गुस्से में बोले-संस्कृत पर गर्व करने के लिए संस्कृत सीखना जरूरी है।यह किस शास्त्र में लिखा है? संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि गर्व करने वाले का भी योगदान जरुरी है।गर्व करना योगदान नहीं है क्या? गर्व करने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है।न कुछ किए भी गर्व हो सकता है।वही हम कर रहे हैं। अपने देश में यही तो कमी रही। सब काम करने में लगे रहे। गर्व की तरफ़ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने बड़े बड़े लोग हुए इस देश में। वे बेचारे बिना गर्व कराए ही चले गए। हमने इस कमी को दूर किया है। अब हमें दूर दूर से गर्व करने बुलाया जाता है। हम जाकर गर्व कर आते हैं।हमारे जैसा गर्व और कोई नहीं कर पाता।आप क्या समझते हैं कि गर्व करना छोटी मोटी बात है। लोग करने वाले को याद नहीं रखते,गर्व करने वाले याद रखे जाते हैं।करने वाला चला जाता है,गर्व करने वाला छा जाता है। करने में सज़ा है, गर्व करने में मज़ा है। अब तो यह हालत है,भाई कि लोग काम शुरू करने के पहले ही गर्व करने वालों को बुला लेते हैं।हम गर्व करते हैं तब वे काम शुरू करते हैं। हमारे गर्व की बड़ी डिमांड है।हम तो एडवांस में भी गर्व कर देते हैं।काम आपको जब करना हो तब करना। गर्व हमसे अभी करवा लीजिए। आपने अभी हमारा हुनर देखा नहीं है। जिन चीजों पर शर्म करना चाहिए हम उन पर गर्व करके दिखा देते हैं। आपको भी कभी गर्व करवाना हो तो हमें सेवा का मौका दीजियेगा। अब आप जाइए,नमस्कार।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

परीक्षा में दिव्यांगों के लेखक बदलने के सवाल पर विचार

संघ लोक सेवा आयोग यह पक्का करेगा कि उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के हर विज्ञापन में एक साफ प्रावधान शामिल किया जाए, जिससे योग्य उम्मीदवार परीक्षा की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले तक लेखक बदलने की रिक्वेस्ट कर सके। साथ ही ऐसी रिक्वेस्ट पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा। इस संबंध में आवेदन के तीन कार्य दिवसों के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा निपटाया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, जिससे दिव्यांग संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवार के लिए स्क्राइब (लेखक) का नाम बदलना आसान हो जाएगा। जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने में भी मदद मिलेगी। न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार, जो स्क्राइब (लेखक) के लिए योग्य हैं, उन्हें परीक्षा से कम-से-कम सात दिन पहले तक लेखक का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करने की इजाजत होगी। इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा में देखने में दिक्कत वाले उम्मीदवार के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए दो महीने के अंदर एक प्लान बनाकर न्यायालय के सामने रखेगा। यूपीएससी लेखक वह व्यक्ति होता है जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाओं के दौरान किसी दिव्यांग उम्मीदवार (जैसे दृष्टिहीनता, चलने-फिरने में अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी) के उत्तर लिखता है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ मेल खाता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने 'मिशन एक्सेसिबिलिटी' नाम की रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया। यह एक ऑर्गनाइजेशन है, जो दिव्यांगों के अधिकारों की वकालत करता है। इस याचिका में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में लेखक रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन में बदलाव करने और योग्य उम्मीदवार के लिए सुलभ डिजिटल प्रश्न पत्र के साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप के इस्तेमाल की इजाजत देने की मांग की गई। गठित की नई कमेटी न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा अयोग ने तब से एक सोच-समझकर आगे बढ़ने वाला फैसला लिया ताकि उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली अलग-अलग परीक्षाओं में देखने में दिक्कत वाले उम्मीदवार को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की सुविधा दी जा सके। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि फैसले को लागू करने में आने वाली कमियों को ठोस योजना, अंतर रिजेंसी सहयोग और एक जैसे स्टैंडर्ड्स बनाने के जरिए दूर किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली परीक्षा में एक्सेसिबिलिटी का लक्ष्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे।

इस पृष्ठभूमि में संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए न्यायालय ने ये निर्देश दिए। संघ लोक सेवा आयोग यह पक्का करेगा

कि उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के हर विज्ञापन में एक साफ प्रावधान शामिल किया जाए, जिससे लेखक के लिए योग्य उम्मीदवार परीक्षा की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले तक लेखक बदलने की रिक्वेस्ट कर सकें। साथ ही ऐसी रिक्वेस्ट पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा। इस संबंध में आवेदन के तीन कार्य दिवसों के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा निपटाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग इस आदेश की तारीख से दो महीने के अंदर एक पूरा अनुपालन शपथ पत्र फाइल करेगा, जिसमें उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देखने में दिक्कत वाले उम्मीदवार के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट और इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित प्लान ऑफ एक्शन, टाइमलाइन और तौर-तरीकों को साफ तौर पर बताया जाएगा।

शपथ पत्र में सभी या तय परीक्षा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और वैलिडेशन के लिए प्रस्तावित स्टेप्स भी बताए जाएंगे। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि यह सुविधा अगले एग्जाम साइकिल से सभी योग्य उम्मीदवार के लिए चालू और उपलब्ध हो, इसकी संभावना कितनी है। संघ लोक सेवा आयोग, दिव्यांगजनों का उत्थान विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी) और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी (एनआईईपीवीडी) के साथ मिलकर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और दूसरी मददगार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक जैसी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल बनाएगा ताकि सभी या पहचाने गए एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी उस प्रकार से पक्की हो सके, जैसा उसे ठीक लगे।

भारत संघ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) और सामाजिक न्याय और उत्थान मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट) के जरिए, ऊपर बताए गए तरीकों को तेजी से लागू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सभी जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल मदद देगा और जहां भी जरूरत होगी, राज्य सरकार और परीक्षा अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। इसे इन तरीकों को इस तरह से लागू किया जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवार को पूरी एक्सेस मिले और परीक्षा प्रोसेस की पवित्रता, गोपनीयता और निष्पक्षता बनी रहे। न्यायालय ने कहा कि गवर्नेंस में सबको शामिल करने के लिए न सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बनाना जरूरी है, बल्कि उन पॉलिसीज को ईमानदारी और असरदार तरीके से लागू करना भी जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, आसान और समाज के हर हिस्से की जरूरतों के हिसाब से सेंसिटिव होंगे। आगे कहा गया, सही मायने में बराबरी का मतलब एक जैसा होना नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को हटाना है, जो लोगों को बराबरी पर खड़े होने से रोकती हैं... दिव्यांग लोगों को दिए गए अधिकार भलाई के काम नहीं हैं, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिए गए बराबरी, सम्मान और भेदभाव न करने के संवैधानिक वादे का इजहार हैं।

भारत के लोगों को दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए बनाये गए कानून, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को जानना चाहिए। यह अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिये भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था। यह अधिनियम पहले के निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लेता है। इसे भारत में दिव्यांगजनों की जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने में अपर्याप्त तथा पुराना माना जाता था। अधिनियम द्वारा शुरू किये गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक दिव्यांगता की परिभाषा और वर्गीकरण का विस्तार है। साथ ही यह अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है। पिछले कानून के तहत यह मात्र सात प्रकार की थी। इनमें अंध और दृष्टि-बाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, श्रवण विकार / दोष, चलन-संबंधी दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्केलेरोसिस, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, श्रवण विकार/दोष, तेजाब हमले से प्रभावित और पार्किन्संस रोग सहित कई दिव्यांगता सम्मिलित थी।

यह कानून केंद्र सरकार को निर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा यह दिव्यांग व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि है, जो बाधाओं के कारण, उन्हें दूसरों के साथ समान समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है। साथ ही बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं है, जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है, जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रामाणित। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता की उच्च आवश्यकता होती है और उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों के लिये दूसरों से सहायता की आवश्यकता होती है। इससे स्पष्ट है कि नए कानून में दिव्यांगता को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। यह देखना रोचक होगा कि नया कानून दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में कौन से परिवर्तन लाने में सफल हो सकेगा।

अनोखा बाजार

ब्रजेश कानूनगो

(लेखक साहित्यकार और ब्लॉगर हैं)

जहां करेंसी नोटों की दुकानें सजती हैं!

हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की। सोमालीलैंड पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्व-घोषित स्वतंत्र देश है, जिसने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमाएं जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया से लगती हैं। इसका इतिहास 1884 से शुरू होता है, जब यह ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया था। 1960 में, यह स्वतंत्र हुआ और सोमालिया के साथ मिलकर सोमाली गणराज्य का गठन किया। हालांकि, 1991 में, सोमालीलैंड ने फिर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और तब से यह एक स्व-घोषित स्वतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसमें एक राष्ट्रपति और एक द्विसदनीय संसद है। देश में नियमित रूप से चुनाव होते हैं और यह अफ्रीका में सबसे अधिक स्थिर और लोकतांत्रिक देशों में से एक माना जाता है।

हम हाट बाजारों में किराना,सब्जियों और हर तरह की रोजमर्रा जरूरतों की चीजों की दुकानें सजा कर व्यापारियों को अपना माल बेचते देखते रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक ट्रेवलर के यूट्यूब वीडियो में देखा तो दंग रह गए कि बाजार में करेंसी नोटों की बहुत सारी खुले आम दुकानें सजी हुई हैं और कोई खास सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं दिखी। नमाज का समय होने पर दुकानदार बिना कोई लूट के डर से निश्चिंत होकर दुकान को खुला छोड़कर मस्ज़िद की ओर चला गया।

हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की। सोमालीलैंड पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्व-घोषित स्वतंत्र देश है, जिसने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमाएं जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया से लगती हैं। इसका इतिहास 1884 से शुरू होता है, जब यह ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया था। 1960 में, यह स्वतंत्र हुआ और सोमालिया के साथ मिलकर सोमाली गणराज्य का गठन किया। हालांकि, 1991 में, सोमालीलैंड ने फिर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और तब से यह एक स्व-घोषित स्वतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसमें एक राष्ट्रपति और एक द्विसदनीय संसद है। देश में नियमित रूप से चुनाव होते हैं और यह अफ्रीका में सबसे अधिक स्थिर और लोकतांत्रिक देशों में से एक माना जाता है।

इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित है। देश में बेरबेरा पोर्ट है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। इसके अलावा, देश में तेल और गैस जैसे खनिज संसाधन भी हैं। मुख्य रूप से यहां की सोमाली संस्कृति में इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें लास गील की चट्टान कला शामिल है।

दरअसल दुकान खुली छोड़कर दुकानदार के नमाज पढ़ने चले जाने का दृश्य सोमालीलैंड के सड़क किनारे लगने वाले मनी मार्केट (पैसे के बाज़ार) जैसी अनोखी जगह का है जहाँ सामान नहीं, बल्कि नोटों के बंडल बेचे जाते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्रा सोमालीलैंड शिलिंग (Somaliland Shilling) की कीमत बहुत कम

और अस्थिर होती गई है, जिससे लोग भारी मात्रा में नकदी लेकर खरीददारी करते हैं, यहाँ तक कि सब्जियों या सोने के लिए भी नोटों की बोरियाँ ले जानी पड़ती हैं, और इसी कारण अब लोग डिजिटल भुगतान (मोबाइल मनी) को भी पसंद करने लगे हैं। हालांकि ये बाज़ार सुरक्षित माने जाते हैं और इनमें खुलेआम लेन-देन होता है।

सोमालीलैंड शिलिंग (SLS) की कीमत इतनी कम है कि .1 एक अमेरिकी डॉलर के बदले 10,000 से 11,000 SLS सोमालीलैंड शिलिंग तक मिलते हैं। नोटों की इतनी बड़ी मात्रा के कारण, दुकानदार अक्सर पैसों को गिनने के बजाय तौलकर लेन-देन करते भी दिखाई देते हैं। नोटों के ये बाज़ार फल-सब्जी की मंडी की तरह लगते हैं, जहाँ लोग नोटों के बंडल खरीदते और बेचते हैं यहां तक कि सब्जियों के लिए भी नोटों से भरे थैले ले जाने पड़ सकते हैं। खास बात यह कि इन बाजारों में लेन-देन खुलेआम होता है और इन्हें सुरक्षित माना जाता है, जहाँ लोग बिना डर के भारी नकदी ले जाते हैं, कभी-कभी तो ठेले (wheelbarrows) में भी।

नोटों की भारी भरकम नकदी जैसी समस्या से बचने के लिए, सोमालीलैंड के लोग अब मोबाइल मनी (जैसे EVC Plus) का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे हैं; यहाँ तक कि भिखारी भी डिजिटल लेनदेन करते पाए जाते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का यह बाज़ार सोमालीलैंड की अर्थव्यवस्था और लोगों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके को दर्शाता है, जहाँ राज्य की संस्थाएँ कमज़ोर हैं और लोग आत्मनिर्भर हैं। इस अनोखे बाज़ार के पीछे मुख्य कारण सोमालीलैंड शिलिंग (SL Shilling) का अत्यधिक अवमूल्यन (Devaluation) और उच्च मुद्रास्फीति होना (High Inflation) है।

संक्षेप में, सोमालीलैंड का यह मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ भौतिक नकदी का मूल्य इतना कम है कि वह एक वस्तु बन जाती है, जिसे खरीदा-बेचा जाता है, और यह उनकी अर्थव्यवस्था की अनूठी वास्तविकता को दिखाता है। ट्रैवलरों के यूट्यूब वीडियो देखते हुए सोमालीलैंड के इस खुले मनी मार्केट को देखकर अचंभित तो हो ही जाते हैं दर्शक।

चाइना डोर का बाजार

अमित राव पवार

युवा लेखक

प्रशासनिक विफलता या संगठित अपराध?

मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है, जो केवल मौसम परिवर्तन या फसल कटाई का उत्सव नहीं है, बल्कि संयम, सादगी और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और यह परिवर्तन हमें अपने जीवन में सकारात्मक दिशा अपनाने का संदेश देता है। पतंगबाज़ी इस पर्व का अभिन्न अंग है, जो स्वतंत्रता, उत्साह और आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रतीक मानी जाती है। किंतु विडंबना यह है कि बीते कुछ वर्षों में यही उत्सव चाइना डोर जैसी जानलेवा सामग्री के कारण भय, शोक और असंवेदनशीलता का प्रतीक बनता जा रहा है।

चाइना डोर–जिसे नायलॉन या कांच लेपित मांझा भी कहा जाता है–आज पतंगबाज़ी की परंपरा को न केवल विकृत कर रहा है, बल्कि इसे खतरनाक भी बना चुका है। यह मांझा इतना धारदार होता है कि मोटी चमड़ी, पक्षियों के पंख, और यहां तक कि बाइक सवारों की गर्दन तक को बेरहमी से काट देता है। हर वर्ष मकर संक्रांति के आसपास देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जिनमें राह चलते लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, कई बार अपनी जान तक गंवा देते हैं। पक्षियों की बात करें तो सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों पक्षी हर साल इस मांझे की चपेट में आकर तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। इन भयावह परिणामों को देखते हुए केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारें वर्षों पहले ही चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं।

इसके निर्माण, आयात, भंडारण और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बावजूद यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है कि जब कानून स्पष्ट है, सजा का प्रावधान मौजूद है, और खतरे सर्वविदित हैं, तो फिर यह जानलेवा मांझा बाजारों में खुलेआम कैसे बिक रहा है, क्या कानून का ख़ौफ़ अपराधियों के लिए खत्म हो गया है?

यह समस्या केवल कानून उल्लंघन की नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और संगठित अपराध की ओर इशारा करती है। चाइना डोर का कारोबार किसी एक गली या मोहल्ले तक सीमित नहीं है। यह एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें सीमा पार से आयात, बड़े गोदामों में भंडारण, थोक आपूर्ति और फिर खुदरा बिक्री तक की पूरी श्रृंखला शामिल है। स्पष्ट है कि यह सब बिना किसी संरक्षण और मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जब भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वह प्रायः केवल फुटकर दुकानदारों या छोटे विक्रेताओं तक ही सीमित रह जाती है। कुछ रीलें बनती हैं, कुछ मांझे जब्त किए जाते हैं और कुछ लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। किंतु असली सवाल यह है कि बड़े व्यापारी, थोक आपूर्तिकर्ता और आयात से जुड़े नेटवर्क हमेशा कानून की पकड़ से बाहर क्यों रहते हैं? क्या प्रशासन की पहुँच वहां तक नहीं है, या फिर जानबूझकर आँखें मूँदी जाती हैं हर वर्ष मकर संक्रांति के समय यही क्रम दोहराया जाता है। कुछ दर्दनाक हादसे होते हैं, मीडिया में शोर मचता है, प्रशासन अचानक सक्रिय दिखने लगता है, और फिर कुछ दिनों बाद

सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। यह अस्थायी सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि समस्या के मूल में जाने की बजाय केवल लक्षणों का उपचार किया जा रहा है। जब तक चाइना डोर के स्रोत, सप्लाई चेन और आर्थिक लाभ उठाने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती।

चाइना डोर केवल मानव जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। पक्षी, जो हमारे पर्यावरण संतुलन के अहम घटक हैं, इस मांझे के सबसे बड़े शिकार बनते हैं। घायल पक्षी घंटों तड़पते रहते हैं, कई बार उनके पंख या गर्दन कट जाती है। यह दृश्य न केवल करुणाजनक है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि मनोरंजन के लिए अन्य जीवों की पीड़ा को अनदेखा कर दें? विडंबना यह भी है कि भारत स्वयं पतंग और मांझे के उत्पादन में आत्मनिर्भर रहा है। पारंपरिक सूती (कॉटन) मांझा न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह स्वदेशी कुटीर उद्योगों से जुड़ा हुआ है। देश के कई राज्यों–जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश–में हजारों परिवार इस उद्योग से अपनी आजीविका कमाते रहे हैं। चाइना डोर के प्रचलन ने न केवल जान-माल को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि इन पारंपरिक कारीगरों की रोज़ी-रोटी भी छीन ली है।

यदि सरकार ठोस नीति बनाकर स्वदेशी और सुरक्षित मांझे को बढ़ावा दे, तो यह समस्या काफी हद तक स्वतः समाप्त हो सकती है। सब्सिडी, प्रचार, और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर न केवल रोजगार बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जानलेवा चाइना डोर को बाजार से बाहर भी किया जा सकता है। 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और प्रशासन केवल प्रतिबंध की घोषणा तक सीमित न रहें, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीरता से ध्यान दें। चाइना डोर के आयात मार्गों की पहचान, अंतरराज्यीय समन्वय, नियमित निगरानी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई इस दिशा में अनिवार्य कदम हैं। साथ ही, ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और उदाहरणात्मक सजा भी जरूरी है, ताकि अवैध कारोबारियों में कानून का भय उत्पन्न हो।

इसके समानांतर जन-जागरूकता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक समाज स्वयं इस खतरनाक मांझे को पूरी तरह नकारेगा नहीं, तब तक प्रशासनिक प्रयास अधूरे रहेंगे। नागरिकों को यह समझना होगा कि पतंगबाज़ी का आनंद किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। माता-पिता, स्कूल, सामाजिक संगठन और मीडिया–सभी को मिलकर इस विषय पर निरंतर संवाद और जागरूकता फैलानी होगी। यदि आज भी हम दिखावटी कार्रवाई और मौसमी सक्रियता में उलझे रहे, तो आने वाले वर्षों में चाइना डोर का प्रभुत्व और अधिक बढ़ेगा। हर मकर संक्रांति किसी न किसी परिवार के लिए मातम लेकर आएगी,और हम केवल शोक संदेशों तक सीमित रह जाएंगे। अब समय आ गया है कि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर यह संकल्प लें कि लाभ के लिए जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

हिन्दू सम्मेलन की दिव्यता-भव्यता और उमड़े सैलाब से धारा नगरी ने रच दिया इतिहास

उत्सव और उल्लास की बेला से बरसों- बरस याद रहने वाली स्मृतियों में अंकित हो गया हिन्दू सम्मेलन...

धार से राजेश शर्मा

राजा भोज की धारा नगरी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए देश और दुनिया में जानी जाती हैं। साहित्य- संस्कृति और शिक्षा की इस वैभवशाली नगरी में 4 जनवरी को उमड़े सैलाब ने एक बार फिर इस ऐतिहासिक नगरी के इतिहास को मानों जीवंत कर दिया। अवसर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की पावन बेला में आयोजित हिंदू सम्मेलन का। उत्सव और उल्लास के रंग में धार की धरा की छटा मनमोहक दिखाई दे रही थी। 14 बस्तियों में एक साथ हुए हिंदू सम्मेलन में उमड़ी उत्सव और उल्लास की बेला से बरसों- बरस याद रहने वाली स्मृतियों में अंकित हो गया हिन्दू संगम। मातृशक्ति, प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, युवाओं, समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों, साधु- संतों की गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन यादगार बन गया। हजारों- हजार हिन्दूजनों की उपस्थिति में शहर सांस्कृतिक जागरण का साक्षी बना।

100 वर्षों में पहली बार ऐसा विराट दृश्य देखने को मिला, जब हजारों हिंदू परिवार एक साथ जुटे- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 4 जनवरी को शहर की 14 बस्तियों में एक साथ आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि धार की सामाजिक चेतना, संगठन शक्ति और सांस्कृतिक विरासत आज भी जीवंत है। पिछले 100 वर्षों में पहली बार ऐसा विराट दृश्य देखने को मिला, जब हजारों हिंदू परिवार एक साथ जुटे और पूरा नगर हिंदुत्व, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव के रंग में रंग गया।

समाज जागरण के महाअभियान का दिया संदेश - सम्मेलनों में शहरी क्षेत्रों के हजारों परिवारों की उपस्थिति ने इसे केवल आयोजन नहीं, बल्कि समाज जागरण का महाअभियान बना दिया। प्रबुद्ध नागरिकों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, समाज के प्रतिष्ठित जनों एवं साधु-संतों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई दी। वक्ताओं ने समाज की एकता, राष्ट्र निर्माण में हिन्दू समाज की भूमिका, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, परिवार संस्था की मजबूती, सेवा कार्य, युवा पीढ़ी में राष्ट्रभाव और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

सुव्यवस्थित आयोजन, अनुशासन बना पहचान- आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बस्ती में अलग-अलग समितियां गठित की गई थीं। स्वागत, मंच संचालन, जलपान, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात–हर स्तर पर अनुशासन और व्यवस्थापन संघ की कार्यशैली को दर्शाता रहा था। पूरे शहर में उत्सव जैसा वातावरण बना रहा और नागरिकों ने स्वस्फूर्त सहभागिता कर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मातृशक्तियों की सहभागिता ने सम्मेलन को दी विशेष पहचान..

हिंदू सम्मेलनों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने न केवल उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, बल्कि विचार, संकल्प और कार्ययोजना के स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभाई। महिला वक्ताओं के उद्बोधन में परिवार संस्था की मजबूती, बच्चों में संस्कार निर्माण, सामाजिक समरसता और सेवाभाव को जीवन का अंग बनाने पर विशेष जोर दिया गया। संस्कारवान समाज की नींव घर से ही पड़ती है और इसमें महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दर्शाती है कि सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नारी शक्ति अग्रणी भूमिका निभा रही है।

दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले व्यवहारिक बदलाव 'पंच परिवर्तन'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हिंदू सम्मेलनों में 'पंच परिवर्तन' को समाज परिवर्तन का मूल मंत्र बताया गया। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि पंच परिवर्तन केवल विचारधारा नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले व्यवहारिक बदलाव हैं, जिनसे सशक्त और संगठित समाज का निर्माण होता है।

1. स्वावलंबन, 2. कुटुंब प्रबोधन , 3. सामाजिक समरसता , 4. पर्यावरण संरक्षण , 5. नागरिक कर्तव्य

वक्ताओं ने कहा कि यदि पंच परिवर्तन को व्यक्ति, परिवार और समाज के स्तर पर अपनाया जाए, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया स्वतः सशक्त हो जाती है।

14 बस्तियों में मिला संतों का सानिध्य व मुख्य वक्ताओं का मार्गदर्शन

वीर तेजाजी बस्ती में मुख्य वक्ता अरविंद चौधरी रहे, जहां संत श्री नृसिंह दास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। राजा भोज बस्ती में राहुल डोडिया मुख्य वक्ता थे तथा संत श्री आचार्य गणेश जी उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल बस्ती में महेश अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन दिया और संत श्री हरिहरानंद जी महाराज का सानिध्य मिला। महाराणा प्रताप बस्ती में मुख्य वक्ता अभिषेक गुप्ता रहे, जहां दंडी स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। त्रिमूर्ति बस्ती में रघुवीर सिंह सिसोदिया मुख्य वक्ता थे तथा चिन्मयानंद मिशन के संतश्री का सानिध्य रहा। वीर सावरकर बस्ती में बाबूलाल हामड़ मुख्य वक्ता रहे और संत श्री गोपाल दास जी महाराज उपस्थित रहे। फड़के बस्ती में मृणाल दोराया मुख्य वक्ता थे तथा संत श्री वासु श्रेष्ठजी का सानिध्य मिला। सुभाष बस्ती में विवेक निंबालकर मुख्य वक्ता रहे और संत श्री श्रवण जी भारती उपस्थित रहे। विवेकानंद बस्ती में गोपाल डोड मुख्य वक्ता थे तथा संत श्री मंगल दास जी त्यागी का सानिध्य प्राप्त हुआ। ज्योतिबा फुले बस्ती में भूपेंद्र कसेरा मुख्य वक्ता रहे और हर्षित मिश्रा उपस्थित रहे। मधुकर बस्ती में भूपेंद्र राठौड़ मुख्य वक्ता थे, जहां श्री गुलाब कोकर्ण महाराज जी का सानिध्य मिला। गुरु गोविंद बस्ती में अंकित गजकेश्वर मुख्य वक्ता रहे और राधे-राधे महाराज उपस्थित रहे। नित्यानंद बस्ती में प्रेम चौधरी मुख्य वक्ता थे तथा गुणानंद जी महाराज का सानिध्य मिला। वहीं शिवाजी बस्ती में तरुण राठौड़ ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन दिया और स्वामी असंघनंदजी राघवेंद्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ।

तेजी से घट रहा वर्धा बांध का जलस्तर

सलाईढाना, कोडर व चिचंडा के किसानों की बढ़ी चिंता

सिंचाई विभाग द्वारा नदी-नालों में छोड़ा जा रहा वर्धा का पानी

बैतूल/मुलताई। करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित वर्धा सिंचाई परियोजना ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। परियोजना का नल-जल घटक अब तक अधर में लटका हुआ है, वहीं बांध घटक को लेकर भी सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विशेष रूप से वर्धा बांध में संचित जल के प्रबंधन को लेकर ग्राम सलाईढाना, कोडर एवं चिचंडा के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों का कहना है कि वर्धा बांध निर्माण में सर्वाधिक भूमि इन्हीं तीन गांवों के किसानों की अधिग्रहित की गई थी। शेष बची भूमि पर किसान लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से फसल उत्पादन कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी जानबूझकर किसानों को लिफ्ट सिंचाई का लाभ न मिल सके, इसके लिए वर्धा बांध का पानी अंबोरी नदी में छोड़ा जा रहा है। यह पानी गोपाल तलाई से नरखेड़ के मध्य स्थित नालों में भी प्रवाहित किया जा रहा है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक निजी ब्लूबेरी कंपनी को बिना समुचित नाप-तौल के जल उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी अपने व्यावसायिक उपयोग हेतु पानी ले रही है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी कारण वर्धा बांध का जलस्तर तेजी से घट रहा है। एक ओर वर्धा का पानी नदी-नालों एवं कंपनी के उपयोग में जा रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान सिंचाई के लिए पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं।

अंबोरी नदी में 10 किलोमीटर तक फैला पानी

ग्राम चिचंडा निवासी मनोज कसारे, मुकेश रबड़े, सुरेंद्र रेबड़े, सुनील पवार, राजू कोड़ले, हरिराम भलावी, ग्राम सलाईढाना निवासी चंदन बरखड़े, राहुल बरखड़े, सोमनाथ बरखड़े, तथा ग्राम कोडर निवासी गुड्डू महाजन, मारुति बेले, नरेंद्र बेले एवं श्रीराम बेले ने बताया कि तीनों गांवों के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि विभाग एक ओर नदी-नालों के माध्यम से पानी बहा रहा है, वही पिछले दो माह से नहर लगातार चालू रखी गई है। सिंचाई विभाग समय पर नहर खोलने और बंद करने की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहा, जिससे भारी मात्रा में जल अपव्यय हो रहा है। किसान चंदन बरखड़े ने बताया कि जब भी किसानो को किसी समस्या को लेकर सिंचाई अधिकारियों से संपर्क करना होता है, वर्धा बांध के एसडीओ चौहान फोन नहीं उठाते। उल्लेखनीय है कि एसडीओ चौहान एक दशक से अधिक समय से मुलताई सिंचाई विभाग में पदस्थ हैं। इस दौरान कई चुनाव और स्थानांतरण हुए, किंतु वे यहीं बने रहे। किसानों का आरोप है कि इतने वर्षों बाद भी वे किसानों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं हैं।वहीं, इस संबंध में सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री सी.एल. मरकाम का कहना है कि सिंचाई अधिकारी किसानों के फोन उठाने के लिए बाध्य नहीं हैं। फोन हमारी निजी सुविधा के लिए रखे जाते हैं।

इनका कहना है -

वर्धा बांध से नदी-नालों में छोड़ा जाने वाला पानी पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से आवश्यक होता है। जल संसाधन विभाग में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। ब्लूबेरी कंपनी को पानी अवैध रूप से नहीं दिया जा रहा है, उनके पास वैध अनुमति है।

- सी.एल. मरकाम,
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मुलताई

नवजात शिशु का शव मिला, अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज

बैतूल। जिला चिकित्सालय बैतूल स्थित शौचालय के चैम्बर में नवजात शिशु का भ्रुण मिला है। जिससे हडक़ंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस तहत के मामला दर्ज कर जांच में लिया है। मर्ग डायरी के अवलोकन एवं प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गर्भ को छुपाने के उद्देश्य से नवजात शिशु के भ्रुण को जिला चिकित्सालय बैतूल स्थित शौचालय के चैम्बर में फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है तथा आरोपी की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएँ समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक हैं। किसी भी परिस्थिति में नवजात शिशु को छोड़ना या उसकी जान लेना गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर कानूनी दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला को अवांछित गर्भ अथवा सामाजिक दबाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो शासन द्वारा उपलब्ध कानूनी, चिकित्सकीय एवं सामाजिक सहायता योजनाओं का सहारा लिया जा सकता है। इस संबंध में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।

11.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

कोहरे के कारण दृश्यता में आई कमी, 9 बजे तक नहीं हुए सूरज के दर्शन

बैतूल। जिलेभर में सुबह घने कोहरे की चादर छाई रही। जिसके कारण कई कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। वहीं रविवार को यहां न्यूनतम तापमान घटकर 11.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि अधिकतम पारा 26 डिग्री दर्ज हुआ। पिछले एक सप्ताह में तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि 3 जनवरी को रात का पारा 12.5 डिग्री और दिन का 26.2 डिग्री दर्ज हुआ। 4 जनवरी को तापमान फिर गिरकर न्यूनतम 11.5 डिग्री और अधिकतम 26.0 डिग्री पर आ गया, जो एक दिन में करीब एक डिग्री की गिरावट दर्शाता है। आसमान पर बादल छाए रहने और उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाएं ठंडक बनाए हुए हैं। दिन में धूप निकलने के बावजूद वातावरण में गलन महसूस हो रही है, वहीं शाम ढलते ही हवाएं और अधिक ठंडी व सिहरन भरी हो जाती हैं।

कोहरे से दृश्यता में आई कमी - घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई है, जिससे सुबह के समय वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों के

अनुसार, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मध्य प्रदेश में सर्दी का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। ठंड और कोहरे का असर खेती पर भी दिख रहा है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार कोहरे और कम धूप से चना और मटर जैसी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। खेतों में नमी बढऩे से फसलों में रोग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों को सुबह के समय छिडक़ाव या सिंचाई से बचने की सलाह दी गई है।

देहगुड़ मंडल केंद्र पर 11 जनवरी को होगा हिंदू सम्मेलन

भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न

बैतूल/आठनेर। देहगुड़ मंडल केंद्र पर आयोजित होने वाले भव्य हिंदू सम्मेलन के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंडल केंद्र पर आसपास के 11 ग्रामों से ग्राम प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हिंदू सम्मेलन को भव्य बनाने कार्यक्रम में अक्कलवाड़ी भैसाघाट, कोपरा, नयेगांव, पांढुर्णा, रजोला खोदरी के

ग्रामीण जन सांस्कृतिक टोली भजन मंडली के साथ सम्मिलित होने जा रहे है। विभिन्न ग्रामों से आए हुए प्रतिनिधियों ने हिंदू सम्मेलन आयोजन की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि इसके निमित्त ग्राम स्तर पर घर घर अक्षत से आमंत्रण भारत माता आरती, वाहन रैली, प्रभात फेरी, ध्वज यात्रा सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा।

शिवाजी बस्ती हिंदू सम्मेलन की तैयारी शुरू

न्यू बैतूल ग्राउंड में हुआ भूमिपूजन

बैतूल। 20 जनवरी को होने वाले शिवाजी बस्ती हिंदू सम्मेलन के लिए न्यू बैतूल ग्राउंड में रविवार को भूमिपूजन हुआ। यह सम्मेलन बैतूल में लगातार हो रहे हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला का हिस्सा है। सकल हिंदू समाज समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से शहर की 13 बस्तियों को विभाजित कर 33 वार्डों के लिए ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भूमिपूजन कार्यक्रम में देशबंधु, मोती, गांधी और शिवाजी वार्ड के बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इसमें पूर्व पार्षदों सहित कई गणमान्य नागरिकों ने भी सहभागिता की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करना बताया गया है। भूमिपूजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की आरती और पूजन के साथ हुई। आयोजकों के अनुसार, 20 जनवरी को न्यू बैतूल ग्राउंड, कोठीबाजार में होने वाले इस भव्य हिंदू सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम तय कर लिया गया है। इसमें सुबह 10 बजे से कलश यात्रा, सुबह 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, दोपहर 12.15 बजे से मुख्य वक्ता का उद्बोधन और दोपहर 1.30 बजे से भोजन प्रसादी का आयोजन होगा। यह आयोजन सकल हिंदू समाज समिति के तत्वावधान में और शिवाजी बस्ती सकल हिंदू समाज के निवेदन पर किया जा रहा है।

नो-मैपिंग मतदाताओं का सत्यापन शुरू, आज 5 जनवरी से होगी सुनवाई

बैतूल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नो-मैपिंग मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके पिछले एसआईआर की मतदाता सूची के विवरण या तो घोषणा पत्र में उपलब्ध नहीं हैं अथवा डाटाबेस से मेल नहीं खाते ऐसे मतदाताओं को 23 दिसंबर से 14 फरवरी के बीच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस तामील कराए जाएंगे। नोटिस की पावती प्राप्त करने के बाद 7 दिवस के भीतर निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत आवश्यकतानुसार नाम जोडऩे या हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बैतूल जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस तामीली के बाद सुनवाई की प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी। नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाताओं को निर्धारित श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6995 नो-मैपिंग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र 129 मुलताई के 1341, 130 आमला के 1331, 131 बैतूल के 2129, 132 घोड़ाडोंगरी के 981 तथा 133 भैंसदेही के 1213 नो-मैपिंग मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है, तो उन्हें स्वयं की जन्म

तिथि अथवा जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। वहीं 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं के साथ-साथ पिता या माता के जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 02 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं, पिता एवं माता के जन्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति भी देना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मतदाता का जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो विदेशी स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता पंजीकरण अथवा प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले मतदाताओं को नागरिकता पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची भी जारी की गई है, जिनमें केंद्र अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र, आधार से संबंधित प्रावधान आयोग के पत्र के अनुसार लागू होंगे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर सही एवं पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची त्रुटिरहित तैयार की जा सके और कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। ईआरओ/एईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र भोपाल के समक्ष की जा सकेगी।

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया है, जो सामान्य नागरिकों के अवलोकन हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ के पास 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक उपलब्ध है। आम नागरिक/मतदाता मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए दावे, मतदाता सूची की किसी प्रवृष्टि में संशोधन अथवा विलोपन हेतु आपत्तियों को 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाईन दावे/आपत्तियों को वेबसाइड के माध्यम से तथा ऑफलाईन दावे/आपत्तियों बीएलओ को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त कार्यक्रम अवधि में सभी दावे आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

अवैध शराब के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही, दिसंबर माह में किए 53 प्रकरण दर्ज

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के.एवं एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन को रोकने और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।इसी क्रम में जिला पुलिस द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है।जिला पुलिस द्वारा माह दिसम्बर 2025 में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के लिए सघन चेकिंग की कार्यवाही की गई और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 53 प्रकरण दर्ज किए गए।इसके साथ ही पुलिस द्वारा 6,52,910 रूपये कीमत की 1072 लीटर मदिरा भी जब्त की गई और 02 मोटरसाइकिल एवं 01 कार जब्त की गई।

ई-टोकन व्यवस्था से खाद मिलना हुआ आसान

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद वितरण में पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में विदिशा जिले की समितियों में खाद भंडारण सुचारु रूप से जारी है। क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जोगी किरोंदा में खाद लेने आए कृषक से ई-टोकन व्यवस्था के संबंध में संवाद किया एवं उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषकों के विचार प्राप्त किए। कृषकों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी खाद वितरण की ई-टोकन की पहल को काफी सराहा जा रहा है।कृषकों को पूर्व में होने वाली असुविधाओं, लंबी कतारों एवं स्टॉक की कमी से निजात प्राप्त हुई है एवं खाद मिलने में सुविधा हुई है।

गैरतगंज में 13 जनवरी को आयोजित होगा जिला स्तरीय युवा संगम मेला

रायसेन (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार 13 जनवरी को जनपद पंचायत गैरतगंज में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है।जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला 13 जनवरी को प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक आयोजित किया गया है।इस युवा संगम मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शासन की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस जिला स्तरीय युवा संगम मेले में नवभारत फर्टीलाइजर भोपाल, भास्कर मण्डीदीप, वर्धमान यॉन मण्डीदीप, इंसुलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मण्डीदीप, यश्यवी ग्रुप मण्डीदीप, सागर मेनिफेक्चर तामोट, होम हेल्प सेंटर रायसेन, हकाई सिकरोटी मण्डीदीप, आर सेठी रायसेन, वोल्वो आयशर वगरोदा, टाटा मोटर्स अहमदावाद, एसआई सिंगरोली जिला रायसेन द्वारा विभिन्न पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी।इसके लिए अनिवार्य योग्यता पदानुसार कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिग्री इंजीनियरिंग है।आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष निर्धारित है।इस अवसर पर ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें विभिन्न स्वरोजगारमूलक विभागों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा और शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

विदिशा एनआरसी वार्ड में कुपोषित बच्चों को पोषण किट का वितरण किया गया

विदिशा (निप्र)। कुपोषण मुक्त विदिशा हेतु कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की नवीन पहल एवं नवाचार पोषण संजीवनी अभियान विदिशा एनआरसी में आज शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसबा द्वारा कुपोषित बच्चों को किट वितरण किया गया।कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता एवं जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया के मार्गदर्शन में जिले में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में गंभीर (तीव्र) कुपोषण से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पोषण संजीवनी अभियान (कुपोषण मुक्त विदिशा)शुरू किया गया है गंभीर कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उक्त कार्यक्रम में जन सहयोग के माध्यम से अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषण किट तैयार करवाया गया है बिना जन सहयोग एवं जन जागरूकता के पोषण से लड़ना आसान नहीं है इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले समाजसेवी जन प्रतिनिधि शासकीय अधिकारियोंध् कर्मचारियों के सहयोग लेते हुए बच्चों के लिए पोषण किट तैयार किया गया है।पोषण किट में कुपोषित बच्चों को तीन माह तक की पोषण सामाग्री प्रदाय की जाती है जिसमें मूंगफली , मिश्रित सत्तू, बेसन ,चावल ,मूंग दाल ,गुड ,तेल, चना ,सोयाबीन बड़ी एवं घी इत्यादि शामिल हैं इसके अतिरिक्त सभी किट में एक टिफिन बॉक्स एवं पानी बोतल भी प्रदाय की जाती है ।

खाद एवं शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु फार्मर आईडी अनिवार्य है, एक भी किसान फार्मर आईडी से न छूटे- कलेक्टर

फार्मर आईडी बनवाने की कलेक्टर ने किसानों से की अपील

ग्रामों में लंबित न रहे फौती नामांतरण का एक भी प्रकरण - कलेक्टर

कलेक्टर ने भैरूंदा जनपद के अनेक ग्रामों में विकास कार्यों, वन व्यवस्थापन एवं फार्मर आईडी कैंप सहित अनेक गतिविधियों का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने भैरूंदा जनपद के अनेक ग्रामों में पहुंचकर विकास एवं निर्माण कार्यों, फॉर्मर रजिस्ट्री, वन व्यवस्थापन सहित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उनका क्रियान्वयन समय-सीमा में, गुणवत्ता के साथ और पारदर्शिता से किया जाए, इसलिए सभी अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. सर्वप्रथम ग्राम सेवनिया पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय परिसरों में स्वच्छता तथा मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसे तत्काल दूर किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्राम महागांव करिमा में फार्मर रजिस्ट्री के लिए लगाए गए कैंप का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने संबंधित पटवारी को निर्देशित किया कि आगामी दिनों में खाद का वितरण ई-टोकन प्रक्रिया से किया जाएगा, जिसके लिए फार्मर आईडी आवश्यक है, इसलिए सहकारी समितियों में पंजीकृत सभी किसानों की फार्मर आईडी शत-प्रतिशत तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान इससे वंचित न रहे, इसके लिए गांव-गांव जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि खाद प्राप्त करने और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है।

इसके पश्चात कलेक्टर ग्राम वासुदेव पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने गांव के दोनों मतदान केंद्रों पर पहुंचकर बीएलओ से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस समय पर तामील किए जाएं, ताकि मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन रह सके। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी ग्राम में फौती नामांतरण का कोई भी प्रकरण लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो पंचायत द्वारा शीघ्र मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए और उसके पश्चात वैध वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में तत्काल दर्ज किए जाएं, जिससे हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इसी क्रम में कलेक्टर ग्राम नवलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा वन व्यवस्थापन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाए और पौधारोपण एवं संरक्षण कार्यों में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्राम गोपालपुर पहुंचकर आयुष विभाग के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण किया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री सुधीर कुशवाह, तहसीलदार श्री सौरभ शर्मा, जनपद सीईओ श्री संजय अग्रवाल, नायब तहसीलदार मो. अनीस कुरैशी सहित राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

नरवाई प्रबन्धन जागरूकता अभियान बना उन्नत खेती का उदाहरण

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता द्वारा चलाई जा रही नरवाई प्रबंधन की मुहिम के चलते विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायत वर्धा के कृषक श्री भूपेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा अपने धान के खेत में शेष फसल अवशेष की नरवाई को न जलाते हुए ग्रामपंचायत स्तर के साथ-साथ सम्पूर्ण जिले में भी उन्नत खेती का प्रदर्शन किया है। श्री धाकड़ द्वारा नरवाई प्रबंधन के अंतर्गत किए जा रहे कृषिगत क्रियाओं को दृष्टिगत रखते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय कृषि अधिकारी श्री लक्ष्मण गुर्जर द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं समय-समय पर किए गए नरवाई प्रबन्धन जागरूकता कार्यक्रम से मिली प्रेरणा से इस रबी वर्ष में नरवाई को न जलाते हुए चने की फसल किस्म त्टळ 204 की बुवाई की गई।

पर्यावरण संरक्षण एवं मृदा नमी का सदुपयोग :

श्री धाकड़ द्वारा उन्नत खेती की परिचय दिया जा रहा है उसमें सम्बंधित कृषक द्वारा कृषि विभाग नटेरन से क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से मिले राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (दलहन) मिशन अंतर्गत चने की त्टळ 204 किस्म का बीज अनुदान पर लिया गया था जिसकी बुवाई धान के खेत में बची नरवाई को रोटावेटर की सहायता से भूमि में मिलाकर की गई एवं खेत की तैयारी के समय पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धान के खेत की नमी का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों से अपील : श्री धाकड़ द्वारा विकासखंड के सभी कृषकों से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला विदिशा के माध्यम से नरवाई प्रबन्धन हेतु उन्नत कृषि यंत्रों के उपलब्धता जिसमें मुख्यतः सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर, श्रेडर इत्यादि कृषिगत क्रियाओं में प्रयोग करने के लिए कृषकों से अपील की गई है साथ ही क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों से भी अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रयास करने हेतु प्रयत्न किए जाएं ऐसी अपील की जा रही है।

नर्मदापुरम में शराब से भरा ट्रक पलटा 28 लाख की 350 पेटी गायब

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर करणपुर के पास 28 दिसंबर को अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक सड़क से नीचे उतर गया था। इस मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। ट्रक में शराब की कुल 1100 पेटियां थीं, लेकिन पुलिस को मौके से 750 पेटी ही मिलीं। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद 350 पेटी शराब चोरी हो गई है। साहिल रोडवेज इंदौर के प्रतिनिधि हेमंत विश्वकर्मा ने सोहागपुर थाने में 350 पेटी शराब चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मौके से करीब 64 लाख 65 हजार रुपए कीमत की 750 पेटी शराब जब्त की थी।

साहिल रोडवेज के हेमंत विश्वकर्मा ने बताया कि बड़वाह (खरगोन) से मैकडॉवेल्स ब्रांड की 1100 पेटियां लोड होकर शहडोल के सरकारी आबकारी वेयरहाउस जा रही थीं। घटना की जानकारी उन्हें 28 दिसंबर को सुबह 9 बजे मिली। जब वे इंदौर से मौके पर पहुंचे, तो पुलिस शराब को दूसरी जगह रखवा चुकी थी। पुलिस ने 750 पेटी जब्त की हैं, जबकि

350 पेटी शराब मौके से अज्ञात लोगों ने चोरी कर ली।

टाइमिंग पर सवाल: 5 किमी चलने में 9 घंटे कैसे लगे : ट्रांसपोर्टर के मुताबिक, ड्राइवर ने 27 दिसंबर की रात 10 बजे सोहागपुर से निकलने की बात कही थी। उनके अनुसार एक्सीडेंट रात 10:30 से 11:30 बजे के बीच हुआ। वहीं, पुलिस और ग्रामीणों को घटना की सूचना 28 दिसंबर की सुबह 7.30 बजे मिली। सवाल उठ रहा है कि जब ट्रक रात 10 बजे सोहागपुर में था, तो महज 5 किमी दूर एक्सीडेंट स्पॉट तक पहुंचने में इतना वक्त कैसे लगा पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर स्थिति साफ कर सकती है।

ट्रक में लोड शराब का परमिट 28 दिसंबर 2025 की सुबह 4:56 बजे तक वैध था। इसके लिए 7,398 रुपए परिवहन शुल्क भी जमा था। हेमंत विश्वकर्मा का कहना है कि ट्रक उनका ड्राइवर देवेंद्र गिरी गोस्वामी (निवासी हाटपीपल्या, देवास) चला रहा था। शराब वैध थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर डरकर भाग गया, जिससे पुलिस ने अवैध परिवहन का केस दर्ज कर लिया। आशंका है कि शराब माफिया या ग्रामीणों ने शराब लूटी है या प्लानिंग के तहत ट्रक नीचे उतारा गया।

पुलिस ने दर्ज किया था अवैध परिवहन का केस : घटना की सूचना पर एसडीओपी संजू चौहान और सोहागपुर थाना प्रभारी ऊषा मरावी मौके पर पहुंची थीं। पुलिस ने ट्रक में मिली 750 पेटियों को दूसरे वाहन में रखवाकर जब्त किया। ड्राइवर के फरार होने के कारण पुलिस ने 14 घंटे बाद अवैध शराब परिवहन का मामला दर्ज किया था।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा नवीन व्यक्तिगत वन अधिकार लंबित दावों और पूर्व के निरस्त व्यक्तिगत वन अधिकार लंबित दावों, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में सम्परिवर्तन की अद्यतन स्थिति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में डीएफओ औबेदुल्लागंज श्री हेमंत रायकवार, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के पास लंबित 34 दावों का पॉलीगन सर्वे पुनः/सूक्ष्म परीक्षण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के पास भेजने के लिए कहा। उपखण्ड स्तरीय समिति को 15 दिवस में इनका निराकरण करना होगा। इसी प्रकार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में सम्परिवर्तन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। जिनमें सात में से पांच प्रकरण लंबित हैं। इनमें रायसेन वन क्षेत्र के दो प्रकरणों में कार्यवाही हो गई तथा औबेदुल्लागंज वन क्षेत्र के शेष तीन प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कहा। यह सातों प्रकरणों को भोपाल वरिष्ठ कार्यालय में भेजा जाएगा, जिनमें एमपी एसीडी से नक्शा प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त बैठक में ग्राम झिरीबहेडा में बेतवा उद्गम स्थल का सामुदायिक दावें पर भी चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा आवेदक की भूमि का सत्यापन, सीमांकन एवं सर्वे कार्य एमपी वनमित्र पोर्टल एप के माध्यम से सूक्ष्म रूप से की जाए। पोर्टल में आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बुजुर्गो का कथन एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार ग्राम वन अधिकार समिति की बैठकों की सूचना सभी सदस्यों को भी दिए जाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समिति के सदस्य, अधीक्षक भू-अभिलेख, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तहत आयोजित शिविरों के कार्यों की गहन समीक्षा

विदिशा (निप्र)। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने आज अपने चेंबर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तहत विदिशा जिले में आयोजित शिविरों में क्रियान्वित कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्राम स्तर पर आयोजित इन शिविरों में सहरिया जनजातीय समुदाय के परिवारों को चिन्हित योजनाओं के लाभ के साथ-साथ पात्रता पर्ची, आधार कार्ड, समग्र आईडी, आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्यों में गंभीरता से कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा है कि जिन ग्रामों में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं वहां किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न ना हो खासकर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में शिविर आयोजित हो रहे हैं वहां विद्युत आपूर्ति सतत बनी रहे ताकि आधार, समग्र और आयुष्मान कार्ड इत्यादि कार्यों में व्यवधान उत्पन्न ना हो पाए

अपर कलेक्टर श्री डामोर ने बैठक के दौरान ग्राम बार आयोजित शिविरों में बनाए गए आधार कार्ड , आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी सहित अन्य कार्यों की ग्राम वार समीक्षा की। उन्होंने शेष रह गए सहरिया जनजातीय परिवार के हितग्राही जिनके आधार कार्ड या आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उन्हें समय सीमा में शिविरों के माध्यम से लाभ दिलाये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

दोस्त का सिर कुचला, फिर पेट्रोल डालकर आग लगाई, नर्मदापुरम में मां की मौत का बदला लिया

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के जावली गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दोस्तों ने युवक को शराब पार्टी के बहाने बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। पहले पत्थर से सिर कुचला, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हत्या की वजह जादू-टोने का शक बताई जा रही है।

मुख्य आरोपी को शक था कि युवक की मां ने जादू-टोना करके उसकी मां को मारा है, जिसका बदला लेने के लिए उसने मर्डर की प्लानिंग की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें दो नाबालिग (17) हैं।

ऐसे रची गई हत्या की साजिश

वारदात 23 दिसंबर की है। मुख्य आरोपी सुशील नागवंशी ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने दोस्त चंदन नागवंशी (21) को शराब पार्टी का लालच दिया। सुशील, साहिल और दो नाबालिग दोस्त को बाइक पर बिठाकर जावली से करीब 40 किलोमीटर दूर मिडघाट के घने जंगल में ले गए। रास्ते में उन्होंने माखननगर रोड स्थित शराब दुकान से बियर और शराब की बोतलें भी खरीदीं।

जंगल में पहुंचने के बाद पांचों ने शराब पी। जब चंदन पूरी तरह नशे में धुत हो गया, तो सुशील और उसके साथी ने एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। चंदन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने शव की पहचान मिटाने की कोशिश की। वे 50 रुपए का पेट्रोल लेकर आए और चंदन के शव पर छिड़ककर आग लगा दी। सबूत नष्ट करने के लिए उन्होंने थोड़ी दूर पर चंदन की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वे वापस गांव आ गए और सामान्य तरह से रहने लगे।

ऐसे हुआ हत्या का खुलासा

चंदन 23 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने 24 दिसंबर को माखननगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। एसपी सांई कृष्णा थोटा ने बताया कि पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो गांव के लोगों ने चंदन को इन युवकों के साथ जाते हुए देखा था। शुरुआत में पूछताछ करने पर आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे और सहयोग करने का नाटक करते रहे।

मोबाइल लोकेशन से पकड़े गए

पुलिस ने जब टेक्निकल एविडेंस खंगाले और सभी आरोपियों की लोकेशन एक साथ मिडघाट के जंगल में मिली, तो सख्ती से पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर 31 दिसंबर को पुलिस मिडघाट के जंगल पहुंची। वहां चंदन की अधजली लाश और जली हुई बाइक बरामद हुई। एएसपी अभिषेक राजन ने बताया कि शव के पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार देर रात चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

मां की मौत और अंधविश्वास

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी सुशील नागवंशी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि एक महीने पहले उसकी मां की मौत हुई थी। उसे शक था कि चंदन की मां ने उसकी मां पर कोई जादू-टोना (टोटका) किया था, जिसके कारण उनकी जान गई। इसी का बदला लेने के लिए उसने दोस्त को मारने की कसम खाई और साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

गर्लफ्रेंड के साथ जाने की झूठी कहानी बताई

हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने मृतक चंदन नागवंशी की गर्लफ्रेंड की कहानी बनाई थी। पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि उसने चंदन को पार्टी के लिए फोन किया था। इसके बाद सभी लोग बाइक से बुधनी की तरफ जंगल में पार्टी करने गए। आरोपी ने यह भी कहा कि बुधनी में चंदन की गर्लफ्रेंड मिली थी और वहीं से चंदन उसका मोबाइल बंद कर गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। यही बात आरोपी साहिल और अन्य आरोपियों ने भी दोहराई। लेकिन जब पुलिस ने इस कहानी की जांच की और तथ्यों की तस्दीक कराई, तो पूरी बात झूठी निकली।

एमपी में शीतलहर का कहर, स्कूलों में पड़ा असर

9.30 बजे के बाद लगेंगी नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं

भोपाल। मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में सुबह 50 मीटर बाद कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि छतरपुर जिले का नौगांव प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी मौसम को देखते हुए भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। तेज ठंड और कोहरे के चलते भोपाल जिले में कल से स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही लगेंगे। यह निर्णय नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी

भोपाल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि यह व्यवस्था सरकारी, प्राइवेट, CBSE, ICSE, अनुदान प्राप्त एवं अन्य सभी स्कूलों पर लागू रहेगी। भोपाल के अलावा नर्मदापुरम, बालाघाट, ग्वालियर, रतलाम, दतिया, धार, गुना, रायसेन, राजगढ़, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना, श्योपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और रीवा में भी कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मालवा, सचखंड, शताब्दी समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। शनिवार को भोपाल में दिनभर घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान गिरा और 11 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

नौगांव में एक रात में पारा 8.3 डिग्री लुढ़का

सर्द हवाओं की वजह से सर्दी भी तेज हो गई है। छतरपुर के नौगांव में बीती रात पारा 2.5 डिग्री पर पहुंच गया। एक ही रात में पारा 8.3 डिग्री लुढ़का। वहीं, राजगढ़ में 5 डिग्री, दतिया में 5.1 डिग्री, पचमढ़ी में 6.4 डिग्री, शिवपुरी में 7 डिग्री, रतलाम में 7.4 डिग्री, श्योपुर-मंडला में 7.6 डिग्री, खजुराहो में 8 डिग्री, खंडवा में 9 डिग्री, गुना में 9.1 डिग्री, धार में 9.2 डिग्री और उमरिया में पारा 9.4 डिग्री रहा। प्रदेश के पांच बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 6.4 डिग्री पहुंच गया। भोपाल में 10.8 डिग्री, इंदौर में 11.8 डिग्री, उज्जैन में 11.4 डिग्री और जबलपुर में 11 डिग्री दर्ज किया गया। इस बार मध्यप्रदेश में नवंबर-दिसंबर की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवंबर में 84 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी तो दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग ने नवंबर-दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है।

रिपोर्टर्स का रन रेट लोकतंत्र में लगाता है चार चांद

सीएम बोले-पत्रकार साथियों की कलम की बाउंसर, शब्दों की गुगली करती है गहरे घाव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पत्रकार साथियों की कलम की बाउंसर, शब्दों की गुगली और रिपोर्टर्स का रन रेट लोकतंत्र में चार चांद लगाता है। हमारा मध्यप्रदेश हमेशा से दमदार खिलाड़ियों और मजबूत पत्रकारों की धरती रहा है। देश हित में पत्रकारिता को दिशा देने वाले प्रदेश के पत्रकारों ने दिल्ली तक को गौरवान्वित किया है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई जैसे कई पत्रकारों का साहित्य और पत्रकारिता में योगदान अनुकरणीय और वंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को भोपाल खेल पत्रकार संघ द्वारा ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर आयोजित 31वें आईईएस- डिजिआना इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल खेल पत्रकार संघ लगातार तीन दशक से इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का निरंतर आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में क्रिकेट मैच के साथ- साथ आत्मीयता की भी वर्षा होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आने की हैट्रिक लगा रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट को निरंतरता देने संस्था का प्रयास सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक श्री ध्रुव नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार श्री मृगेंद्र सिंह, श्री विजय दास, श्री तेजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष श्री रवीन्द्र यति, समाजिक कार्यकर्ता श्री राहुल कोठारी सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी, अधिकारी, पत्रकार और खेल प्रेमी उपस्थित थे।

ब्राजील-इजराइल की खेती देखने जाएंगे एमपी के किसान

सीएम ने बनाया किसान कैलेंडर, आय बढ़ाने सरकार का बड़ा प्लान

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है कि लक्ष्य सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन और कृषि को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है। इसके लिए 3 साल का रोडमैप तय कर गतिविधियां चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री निवास में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में तय किया है कि खेती से जुड़े सभी विभाग कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य और ऊर्जा आपसी समन्वय से काम करेंगे। किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य और संभाग स्तर पर प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट कराई जाएंगी। सरकार किसानों को देश के उन्नत कृषि राज्यों के साथ-साथ इजराइल और ब्राजील जैसे देशों में आधुनिक खेती, पशुपालन और तकनीकी नवाचार देखने भेजेगी।

सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित करते हुए साफ किया है कि हर योजना का अंतिम लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना होगा। इसके लिए कृषि गतिविधियों को तीन साल के लक्ष्य के साथ संचालित किया जाएगा। खेती को सिर्फ उत्पादन तक सीमित न रखकर बाजार, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से जोड़ा जाएगा, ताकि किसान को उपज का बेहतर दाम मिल सके। खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को प्रोत्साहित कर पानी की बचत के साथ उपज बढ़ाने की योजना है।

सस्ता कर्ज और बेहतर बाजार

सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही बेहतर बाजार नेटवर्क विकसित कर किसानों को उनकी उपज का वाजिब और प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने की रणनीति बनाई गई है। खेती से जुड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उद्यानिकी विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होगा। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस रहेगा। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और श्रीअन्न (मिलेट्स) उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।साथ ही पारंपरिक कृषि ज्ञान और जैव विविधता के संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। खेती के साथ-साथ फूलों की खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ाया जाएगा।

सतना में 'बुलेट राजाओं' के अरमानों पर चला रोड रोलर

अवैध साइलेंसरों से जमीन पर लिखा-ध्वनि प्रदूषण, फिर चला रोड रोलर

सतना। सड़कों पर बुलेट से 'पट-पट' और गोली जैसी आवाज निकालकर दहशत फैलाने वाले मनचलों को सतना पुलिस ने करारा जवाब दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में अभियान चलाकर जब्त किए गए 125 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसरों पर भारी-भरकम रोड रोलर चलवाकर उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया है। यह कार्रवाई कोठी-चित्रकूट मार्ग स्थित यातायात थाने में की गई। शनिवार को यातायात थाने का नजारा देखने लायक था। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में चेकिंग के दौरान रॉयल एनफील्ड (बुलेट) और अन्य

बाइकों से उतरवाए गए 125 से ज्यादा अवैध साइलेंसर जमा किए थे। पुलिसकर्मियों ने इन लोहे के साइलेंसरों को जमीन पर बिछाकर अंग्रेजी में ध्वनि प्रदूषण लिखा। यह संदेश देने की कोशिश थी कि ये यंत्र सिर्फ शोर और बीमारी बांट रहे हैं। इसके बाद एक भारी रोड रोलर मंगाया गया और देखते ही देखते सभी महंगे मॉडिफाइड साइलेंसरों को कुचलकर समतल कर दिया गया।

युवाओं में है 'गोली' वाली आवाज का क्रेज- आजकल के युवाओं में कंपनी फिटेड साइलेंसर हटाकर बाजार से तेज आवाज वाले साइलेंसर लगवाने का चलन बढ़ गया है। ये मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि अचानक निकलने वाली 'पटाखे' या 'गोली' जैसी आवाज से राहगीर, बुजुर्ग और दिल के मरीज घबरा जाते हैं।

खोए हुए 326 मोबाइल लौटाए तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान

क्राइम ब्रांच ने लोगों को दिया नए साल का तोहफा

इंदौर। क्राइम ब्रांच ने जिन लोगों के मोबाइल गुम गए थे, उन्हें नए वर्ष में तोहफा दिया है। ऐसे 326 लोगों को मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे पर खुशियां लौट आई। यह संभव हो सका, पुलिस द्वारा संचालित सिटीजन कॉप एप्लीकेशन से।

से भी प्राप्त किए। इनमें आईफोन, वनप्लस, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी जैसी नामी कंपनियों के महंगे स्मार्टफोन शामिल हैं।

कंपनीवार आंकड़ों में सबसे अधिक वीवो (117), ओप्पो (61), रियलमी (36), रेडमी (26) और सैमसंग (27) मोबाइल शामिल हैं।

इस एप पर पीड़ित लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। लौटाए गए मोबाइलों की कीमत एक करोड़ 20 लाख रुपए है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में सिटीजन कॉप एप पर प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में वर्ष 2025 में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए यह उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई। बरामद मोबाइल मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों बता दें, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड ऐप है, जिसे आम नागरिक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नागरिक रिपोर्ट एन इंसीडेंट और रिपोर्ट लॉस्ट आर्टिकल जैसी सुविधाओं का उपयोग कर घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गुम मोबाइल की शिकायत पर ऑनलाइन रसीद और शिकायत क्रमांक तुरंत मिल जाता है, जिसका उपयोग सिम बंद कराने या नई सिम लेने में किया जा सकता है। इससे थाने के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती।

जमीन विवाद में खंडवा में युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा

हाईटेंशन लाइन टावर पर चढ़कर पूर्व एमएलए पर लगाए आरोप

भोपाल। खंडवा जिले के जूनापानी गांव में ऐसा मामला सामने आया जिससे हड़कंप मच गया। यहां जमीन विवाद के चलते एक युवक हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक ने खंडवा के पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा पर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और हालात को संभालने में जुट गया। युवक के टावर पर चढ़ने से क्षेत्र में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। जूनापानी निवासी रोहित उर्फ पिंटू पाल का कहना है कि उसकी करीब ढाई एकड़ जमीन पर पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा कब्जा करने पहुंचे थे। रोहित का दावा है कि यह जमीन उसके परिवार के कब्जे में पिछले लगभग 100 वर्षों से है और वह वर्षों से इस पर खेती करता आ

रहा है। शनिवार शाम पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा राजस्व विभाग और पुलिस अमले के साथ जमीन का कब्जा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान विरोध जताते हुए रोहित पाल हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया।

मौके पर पहुंचा पुलिस और राजस्व अमला- घटना की जानकारी मिलते ही जावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार और पटवारी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने युवक को समझाइश देकर नीचे उतरने का प्रयास किया। काफी देर तक युवक टावर पर चढ़ा रहा और पूर्व विधायक के खिलाफ आक्रोश दिखाता रहा। हाईटेंशन लाइन के कारण किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रही, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभालता रहा।

पहले भी हो चुकी है टकराव की स्थिति

किसान रोहित पाल का कहना है कि इससे पहले भी विधायक रहते हुए देवेंद्र वर्मा ने राजस्व अमले के साथ जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की थी। उस दौरान भी रोहित पाल ने विरोध जताते हुए हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। हाल ही में तहसीलदार न्यायालय ने इस मामले में पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट के आदेश के आधार पर शनिवार को जमीन का कब्जा दिलाने की कार्रवाई शुरू की गई। जैसे ही कब्जे की प्रक्रिया आगे बढ़ी, रोहित पाल ने फिर से विरोध शुरू कर दिया और हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई को रोक दिया।

भाजपा सभी को साथ लेकर चलती है, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी : हितानंद

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भोपाल जिले के विभिन्न टोलियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने राज्य, जिले और विधानसभा क्षेत्र से लेकर बूथ को मजबूत और सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा, क्योंकि बूथ की मजबूती ही हमें सभी चुनावों में ऐतिहासिक विजय दिलाती है। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जो सभी को साथ लेकर चलती है। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इसलिए बन सकी है, क्योंकि वह सभी समाज वर्गों को साथ लेकर चलती है। हमें व्यक्ति निर्माण और कार्यकर्ता निर्माण को मूल में रखकर अपनी विचारधारा को लेकर निरंतर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन शून्य से शुरू होकर आज विराट वट वृक्ष बना है, इसका श्रेय भी हमारे पार्टी के पितृ पुरूषों, वरिष्ठों के साथ कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत व परिश्रम को जाता है।

भारत को और सशक्त बनाने अपने बूथ को और मजबूत बनायें- भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सभी को साथ लेकर चलती आ रही है। कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर उन्हें जो

जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वही कार्यकर्ता निर्माण और व्यक्ति निर्माण की शुरूआत है। कार्यक्रमों को अपनी विचारधारा को आगे रखकर बेहतर तरीके से संपन्न कराने वाले कार्यकर्ता ही आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। भारत वशुधैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण की अवधारणा को लेकर कार्य करने वाला देश है। ऐसे में भारत विश्व का कल्याण करें, इसके लिए हमें अपने राष्ट्र को मजबूती देनी होगी। भारत को मजबूती तभी मिलेगी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश की बागडोर को संभाले रखें। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश का नेतृत्व करते रहें, इसके लिए हमें भाजपा संगठन को अपने बूथ पर इतना मजबूत करना होगा।

कार्यों की समीक्षा से और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है- भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कार्यकर्ता जब अपने किए हुए कार्यों की स्वयं समीक्षा करते हैं तो वास्तविकता का पता चलता है। समीक्षा करने से यह भी पता चलता है कि जो सोचा था, वह हुआ कि नहीं। हर व्यक्ति को अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा व सिंहावलोकन से कार्यों को आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यकर्ता आधारित संस्कृति ही भाजपा को आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया है।

बैठक में जिला प्रभारी श्री महेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष श्री रविन्द्र यति, जिला महामंत्री श्री किशन सूर्यवंशी एवं श्री जगदीश यादव मंचासीन रहे।

बूथ से विधानसभा तक सक्रिय भूमिका निभाएं कार्यकर्ता : डॉ. महेन्द्र सिंह

संगठन की ताकत से ही साकार होगा विकसित भारत का संकल्प

मुरैना/भिण्ड/ग्वालियर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने रविवार को मुरैना, भिण्ड एवं ग्वालियर जिलों की विभिन्न विधानसभाओं में आयोजित महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने मुरैना जिले के अम्बाह में दिमनी एवं अम्बाह, भिण्ड जिले के मेहगांव में मेहगांव एवं गोहद तथा भिण्ड में भिण्ड, अटेर, लहार एवं ग्वालियर में विभिन्न विधानसभा की बैठकों में संगठनात्मक विषयों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका सशक्त संगठन है और संगठन की मजबूती से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की आगामी कार्ययोजना जनसंपर्क, संगठन विस्तार तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर केंद्रित है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों और कार्ययोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और विधानसभा स्तर पर सक्रिय रहकर

कार्य करना होगा। संगठनात्मक प्रवास, नियमित बैठकें और जनसंवाद के माध्यम से भाजपा की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जनकल्याण और सुशासन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आगामी कार्ययोजना के अंतर्गत इन उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता विशेष अभियान चलाकर कार्य में जुट जाएं।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। इसलिए लाभार्थियों से निरंतर संवाद स्थापित कर योजनाओं की जानकारी देना और पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने में सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संगठन में अनुशासन, समयबद्धता और आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर विशेष बल दिया। आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की कार्ययोजना दीर्घकालिक दृष्टि पर आधारित है। संगठन विस्तार, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, युवा एवं महिला सहभागिता बढ़ाना तथा सोशल और डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि 'हर घर भाजपा' के लक्ष्य के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।